राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

स्वतंत्र प्रभात

जो लिखेगा, वही टिकेगा

@swatantraprabhatmedia | @swatantramedia | RNI.No. UHIN/2012/43078 (epaper.swatantraprabhat.com) | @SwatantraPrabhatonline | news@swatantraprabhat.com

सीतापुर से प्रकाशित एंव अयोध्या ,प्रयागराज ,मिर्जापर ,गोरखपुर , बरेली ,बुंदेलखंड , उत्तराखंड , देहरादून

सीतापुर, शुक्रवार, 11 अप्रैल 2025

वर्ष 14, अंक 2, पृष्ट 12, मूल्यः 03 रुपया

www.swatantraprabhat.com

गाज़ियाबाद , दिल्ली , हरियाणा , चंडीगढ़ , झारखण्ड , बिहार , मध्य प्रदेश ,असम, तेलंगाना आदि जनपदो में प्रसारित

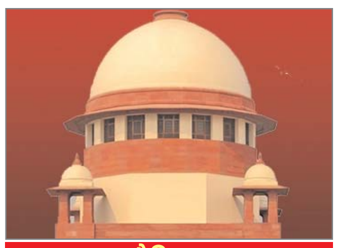

स्वतंत्र प्रभात दैनिक अख़बार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें........
9511151254

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बयान को लेकर समाजवादी महिला सभा 03

ओडिशा के मुख्यमंत्री की नई दिल्ली यात्रा से औद्योगिक क्षेत्र में 04

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए 10 विधेयकों को आरक्षित करने का फैसला खारिज किया

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तमिलनाडु के राज्यपाल डॉ. आर.एन. रवि द्वारा 10 विधेयकों पर अपनी सहमति रोके रखना, जिनमें से सबसे पुराना विधेयक जनवरी 2020 से लंबित है तथा राज्य विधानमंडल द्वारा पुनः अधिनियमित किए जाने के बाद उन्हें राष्ट्रपति के पास सुरक्षित रखना, कानून की दृष्टि से अवैध और त्रुटिपूर्ण है तथा इसे खारिज किया जाना चाहिए।उक्त दस विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा उठाए गए किसी भी परिणामी कदम को भी कानून की दृष्टि से असंवैधानिक घोषित किया गया। कोर्ट ने घोषित किया कि दस विधेयकों को राज्य विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने के पश्चात दूसरे चरण में प्रस्तुत किए जाने पर राज्यपाल की स्वीकृति प्राप्त मानी जाएगी। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि राज्यपाल ने सद्भावना से काम नहीं किया, क्योंकि विधेयकों को राष्ट्रपति के पास भेजा गया, जबकि राज्यपाल ने खुद लंबे समय तक उन पर विचार किया और पंजाब राज्यपाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद उन्हें राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि राज्यपाल विधेयकों पर विचार करके उन्हें वीटो नहीं कर सकते। जस्टिस पारदीवाला द्वारा लिखे गए फैसले में कहा गया कि संवैधानिक योजना के तहत पूर्ण वीटो या पॉकेट वीटो की कोई अवधारणा नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार, राज्यपाल से विधेयकों पर कार्रवाई के तीन तरीकों में से एक को अपनाने की अपेक्षा की जाती है - विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना, विधेयकों पर स्वीकृति रोकना या विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करना। न्यायालय ने माना कि विधेयक को केवल पहली बार में ही

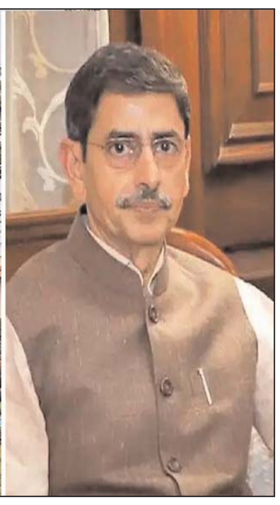

राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किया जा सकता है। जस्टिस पारदीवाला ने निर्णय पढ़ते हुए कहा,÷सामान्य नियम के अनुसार, विधानसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात सरकार द्वारा विधेयक को पुनः प्रस्तुत किए जाने के पश्चात राज्यपाल द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना संभव नहीं है। एकमात्र अपवाद तब होता है, जब दूसरे चरण में प्रस्तुत किया गया विधेयक पहले चरण से भिन्न होता है। निर्णय में न्यायालय ने विधानसभा द्वारा भेजे गए विधेयकों पर अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल के निर्णय के लिए समय-सीमा भी निर्धारित की है, जो इस प्रकार है÷

1. मंत्रिपरिषद की सहायता एवं सलाह से राष्ट्रपति के लिए स्वीकृति रोके जाने एवं उसे आरक्षित किए जाने की स्थिति में राज्यपाल को अधिकतम एक माह की अवधि में निर्णय लेना होता है। 2. राज्य सरकार की सलाह के विपरीत विधेयक को रोके जाने अथवा राष्ट्रपति के लिए आरक्षित किए जाने की स्थिति में राज्यपाल को अधिकतम तीन माह की अवधि में निर्णय लेना होता है। 3. राज्य विधानसभा द्वारा पुनर्विचार के पश्चात विधेयक प्रस्तुत किए जाने की स्थिति में राज्यपाल को एक माह के भीतर विधेयक को स्वीकृति देनी होती है। राज्यपाल को राज्य सरकार की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। न्यायालय ने माना कि सामान्य नियम के अनुसार, राज्यपाल को अनुच्छेद 200 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के अनुसार कार्य करना होता है। राज्यपाल के पास कोई विवेकाधिकार नहीं है। विधेयकों के पुनः अधिनियमित होने के बाद उन्हें अनिवार्य रूप से सहायता और सलाह पर कार्य करना होता है।एकमात्र अपवाद तब है, जब विधेयक अनुच्छेद 200 के दूसरे प्रावधान (हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को प्रभावित करने वाले विधेयक) के अंतर्गत आते हैं। फैसले में कहा गया कि -1. राज्य विधानमंडल द्वारा पुनर्विचार के पश्चात 28.11.2023 को राष्ट्रपति के विचार के लिए विधेयकों को स्वीकृति न देना या आरक्षित रखना, अनुच्छेद 200 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का उल्लंघन है, इसलिए इसे विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण, असंवैधानिक घोषित किया जाता है। इस प्रकार इसे अपास्त किया जाता है। 2. उपर्युक्त निष्कर्ष के परिणामस्वरूप, इन दस विधेयकों पर राष्ट्रपति द्वारा उठाए गए किसी भी परिणामी कदम को भी समान रूप से अमान्य माना जाता है तथा इसे रद्द किया जाता है। 3. राज्यपाल द्वारा इन विधेयकों को स्वीकृति न दिए जाने की अंतिम घोषणा से पहले, जिस अनावश्यक रूप से लंबे समय तक लंबित रखा गया तथा राज्यपाल द्वारा पंजाब राज्य में इस न्यायालय के निर्णय के प्रति दिखाए गए अल्प सम्मान तथा उनके कार्यों के निर्वहन में अन्य बाह्य विचारों को देखते हुए हमारे पास संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा, जिससे इन दस विधेयकों को स्वीकृत मान लिया जाए। 4. हम राज्यपाल के पद को कमतर नहीं आंक रहे हैं। हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि राज्यपाल को संसदीय लोकतंत्र की स्थापित परंपराओं के प्रति उचित सम्मान के साथ काम करना चाहिए, विधायिका के माध्यम से व्यक्त लोगों की इच्छा का सम्मान करना चाहिए और साथ ही लोगों के प्रति उत्तरदायी निर्वाचित सरकार का भी सम्मान करना चाहिए। उन्हें मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक की अपनी भूमिका को निष्पक्षता के साथ निभाना चाहिए, राजनीतिक लाभ के विचारों से नहीं बल्कि अपने द्वारा ली गई संवैधानिक शपथ की पवित्रता से निर्देशित होना चाहिए।

मोगा सेक्स स्कैंडल में एसएसपी, एसपी समेत पंजाब के 4 पूर्व पुलिस अधिकारियों को जेल की सजा

स्वतंत्र प्रभात

मोहाली की एक विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को 2007 के बहुचर्चित मोगा सेक्स स्कैंडल मामले में भ्रष्टाचार और जबरन वसूली के आरोप में तत्कालीन एसएसपी और एसपी समेत पंजाब के चार पूर्व पुलिस अधिकारियों को सजा सुनाई। उन्हें 29 मार्च को दोषी ठहराया गया था। यह सेक्स स्कैंडल 2007 में तब प्रकाश में आया जब मोगा में कुछ प्रभावशाली लोगों पर नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया और फिर उन्हें छोड़ दिया गया। मोगा के पूर्व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) दविंदर सिंह गरचा और पूर्व पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) परमदीप सिंह संधू को पांच-पांच साल कैद और दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। अदालत ने गरचा और संधू को भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम की धारा 13(1) और 13(2) के तहत दोषी पाया। अदालत ने मोगा के सिटी थाने के पूर्व एसएचओ रमन कुमार को आठ साल कैद और तीन लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पूर्व इंस्पेक्टर अमरजीत सिंह को छह साल छह महीने कैद और ढाई लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई। कुमार और सिंह को भ्रष्टाचार निवारण (पीसी) अधिनियम और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 384 (जबरन वसूली) के तहत दोषी ठहराया गया। सिंह को आईपीसी की धारा 511 (आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराध) के तहत भी दोषी पाया गया।हालांकि, अदालत ने अकाली नेता बरजिंदर सिंह उर्फ मक्खन और सुखराज सिंह को सभी आरोपों से बरी कर दिया।

अभियोजन पक्ष की ओर से सीबीआई के सरकारी वकील अनमोल नारंग पेश हुए। यह सेक्स स्कैंडल 2007 में प्रकाश में आया था और कथित तौर पर इसमें राजनेता, स्थानीय नेता, प्रमुख व्यवसायी, प्रभावशाली लोग और यहां तक कि मोगा शहर के पार्षद भी शामिल थे। शहर के कुछ प्रभावशाली लोगों पर नाबालिग लड़कियों के यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया और फिर उन्हें छोड़ दिया गया। पूछताछ में पता चला कि दो महिलाओं, मनप्रीत कौर और मनजीत कौर को कथित तौर पर आरोपियों द्वारा जाल के रूप में इस्तेमाल किया गया था, जो फिर प्रभावशाली लोगों को ब्लैकमेल करती थीं या रिश्वत लेने के बाद उन्हें छोड़ देती थीं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मामला दर्ज किया था। 11 दिसंबर, 2007 को, अदालत ने राजनीतिक और प्रशासनिक प्रभाव के कारण राज्य पुलिस की निष्पक्ष जांच करने की क्षमता पर चिंता जताते हुए जांच को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया। नतीजतन, सीबीआई ने आईपीसी की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ पीसी अधिनियम, 1988 की धारा 7 और 13 (2) के तहत एक प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की। जांच से पता चला कि दविंदर सिंह गरचा, परमदीप सिंह संधू, अमरजीत सिंह और रमन कुमार ने कथित तौर पर अकाली नेता तोता सिंह के बेटे बरजिंदर सिंह और अन्य के साथ मिलकर अवैध वित्तीय लाभ प्राप्त करने की साजिश रची। पूर्व पुलिस कर्मियों ने झूठे एफआईआर दर्ज किए और निर्दोष व्यक्तियों को मामलों से बाहर करने के लिए रिश्वत ली। साजिश के हिस्से के रूप में झूठे हलफनामों का भी इस्तेमाल किया गया।

मुकदमे के दौरान मनप्रीत कौर को सरकारी गवाह बनाया गया था, लेकिन बाद में अदालत ने उसे पक्षद्रोही गवाह घोषित कर दिया, जिसके कारण उसके खिलाफ अलग से कानूनी कार्यवाही शुरू हो गई। इस बीच, रणबीर सिंह उर्फ रानू और करमजीत सिंह बाथ ने अभियोजन पक्ष के गवाह के तौर पर गवाही दी। मुकदमे के दौरान एक अन्य आरोपी मनजीत कौर की मौत हो गई।

संक्षिप्त ख़बरें

निःशुल्क होम्योपैथिक स्वास्थ्य परीक्षण एवं दवा वितरण शिविर का आयोजन 10 अप्रैल को

ब्यूरो प्रयागराज। आयुष आपके द्वार कार्यक्रम के अन्तर्गत राजकीय होम्योपैथिक जिला अस्पताल के सौजन्य से राजकीय मोतीलाल नेहरू मण्डलीय चिकित्सालय (काल्विन), प्रयागराज के परिसर में दिनांक 10 अप्रैल, 2025 को सुबह 08:00 बजे से अपरान्हन 03:00 बजे तक निःशुल्क होम्योपैथिक चिकित्सा स्वास्थ्य परीक्षण एवं दवा वितरण शिविर का आयोजन किया गया हैं।

आंगनबाड़ी भर्ती और बर्तनों की गुणवत्ता को लेकर विभाग पर उठे सवाल

मथुरा। जिला कार्यक्रम अधिकारी मथुरा हमेशा चर्चा में रहते हैं अभी हाल में आंगनबाड़ी भर्ती और केंद्रों को मिले बर्तनों की गुणवत्ता को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं गौरतलब है कि जनपद में अभी आंगनबाड़ी भर्ती चल रही है जिसमें मगोर्रा इलाके गांव की एक घर से तीन महिलाओं को नियुक्त कर दिया है इन नियुक्तियों को लेकर उप जिला अधिकारी गोवर्धन को शिकायती पत्र सोंपा है शिकायत के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी मथुरा को जांच के लिए नियुक्त किया है जिनके खिलाफ शिकायत थी उन्हीं को जांच अधिकारी नियुक्त कर के स्वत÷ सवाल खड़े हो गए हैं इसी प्रकार बलदेव क्षेत्र की एक महिला आंगनबाड़ी भर्ती हुई है महिला को विधवा दर्शाया है। इस प्रकार की तीसरी शिकायत केंद्रों को मिले बर्तनों की गुणवत्ता को लेकर हुई है जिसमें में खराब गुणवत्ता के बर्तनों की खरीदारी कर भेज दिए हैं। बर्तनों को खरीदने के लिए शासन से बड़ा मोटा बजट जनपद के लिए मिला है इन सभी पूरे मामलों को लेकर बुद्धि मिश्रा जिला कार्यक्रम अधिकारी मथुरा से पूछा गया तो उन्होंने बताया आंगनबाड़ी भर्ती में सरकार द्वारा निर्धारित मानकों का प्रयोग हुआ है शैक्षिक योग्यता 12वीं पास हो, विधवा और बीपीएल कार्ड धारक को पहले प्राथमिकता दी जाएगी दोनों मामलों में विधवा और बीपीएल कार्ड धारक हैं बलदेव में महिला के पति के नाम के आगे विभाग की गलती से स्वर्गीय लिख गया है लिस्ट पर व्हाइटनर लगाने पर भी बताया कोर्ट केस में जिन महिलाओं के नाम शामिल हैं उनको नियुक्ति पत्र रोक दिया है श्रीमती मिश्रा ने बताया बर्तनों की गुणवत्ता के सवाल पर शासन से 82 लाख रुपए आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए बर्तन खरीदने का बजट मिला था 4100 रुपए में 30 प्लेट, 30 चम्मच, 30 ग्लास, दो बड़े भगोना 10 लीटर ढक्कन सहित खरीदे गए हैं और 9 आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए गैस चूल्हा सहित बर्तन 10000 की राशि में खरीदारी हुई है।

भाजपा के स्थापना दिवस पर आयोजित हुआ सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन

स्वतंत्र प्रभात

लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी के 46 में स्थापना दिवस के अवसर पर लखनऊ जिले की विधानसभा बक्शी का तालाब में सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन का आयोजन किया गया सम्मेलन का शुभारंभ एवं अध्यक्षता जिला अध्यक्ष विजय मौर्य के द्वारा की गई सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन में तीन चरणों में तीन अलग-अलग वक्ताओं ने अपने-अपने विषय पर उपस्थित सक्रिय सदस्यों को संबोधित किया प्रथम सत्र पूर्व राज्य मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार वीरेंद्र तिवारी ने अपने विषय भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाया गया परिवर्तन विषय पर बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी राजनीतिक दल है जो भारत को एक सुदृढ़ समृद्ध एवं शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर

स्थापित करने के लिए कृत संकल्पित है द्य दूसरे सत्र मैं मैं क्षेत्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह के द्वारा द्वारा भाजपा का चुनावी एवं संगठन विस्तार विषय पर बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए हर चुनाव एक युद्ध की तरह है उन्होंने कहा कि भारतीय लोकतंत्र की भीड़ में बहुत सारे दल विचरण कर रहे हैं लेकिन भाजपा अकेली राष्ट्रीय पार्टी है जिसे विचारधारा और पॉलिटिक्स के आधार पर अलग से पहचाना जाता है वही वही तृतीय सत्र को विधायक योगेश शुक्ला द्वारा संबोधित किया गया उन्होंने अपने विषय प्रधानमंत्री मोदी के साथ 11 वर्षों में विकसित भारत की यात्रा केंद्र एवं प्रदेश सरकार की उपलब्धियां पर बोलते हुए कहा कि कि जितना विकास 65 सालों में नहीं हुआ उससे ज्यादा विकास भाजपा सरकार के द्वारा किया गया विधायक बीकेटी ने बताया कि पहले से ज्यादा महिलाओं का सम्मान एवं स्वाभिमान बढ़ा है इस अवसर पर अरविंद यादव जिला अभियान संयोजक , के के अवस्थी विधानसभा अभियान संयोजक,विवेक सिंह विधानसभा संयोजक बीकेटी,संदीप यादव मण्डल अध्यक्ष बीकेटी, अक्षय मौर्य मण्डल अध्यक्ष चिनहट, कुलदीप सिंह मण्डल अध्यक्ष कुम्हरांव,राजेंद्र लोधी मण्डल इटौंजा, रवि तिवारी जिला उपाध्यक्ष, मनोज प्रजापति जिला उपाध्यक्ष, किसान मोर्चा क्षेत्रीय अध्यक्ष अरुण सिंह गप्पू, संजय सिंह पूर्व प्रत्याशी बीकेटी, संजेश सिंह एवं भारी संख्या में सक्रिय सदस्य एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

स्वर्णिम साहित्य रामोत्सव सम्मान से सम्मानित हुए योगाचार्य धर्मचंद्र

स्वतंत्र प्रभात

प्रयागराज। रामनवमी के शुभ अवसर पर आर्या पब्लिकेशन लखनऊ के संस्थापक सौरभ पांडे के द्वारा योगाचार्य धर्मचंद्र को स्वर्णिम साहित्य रामोत्सव सम्मान से सम्मानित किया गया।। सौरभ पांड ने कहा कि साहित्य समाज का दर्पण है। आज जहां साहित्य के नाम पर अश्लीलता की भरमार है वही योगाचार्य धर्मचंद्र द्वारा लिखित साहित्य समाज में सद प्रेरणा का माध्यम बना हुआ है। योगाचार्य धर्मचंद्र ने कहा कि भगवान राम के जीवन को आज समाज की आवश्यकता है। भगवान राम सिखाते हैं कि भाई भाई के क्या कर्तव्य होने चाहिए पिता पुत्र के कर्तव्य कैसे होने चाहिए ? समाज में टूटती पारिवारिक व्यवस्था को भगवान राम के आदर्शों पर चलकर एक किया जा सकता है। मौके पर उपस्थित शांतिकुंज हरिद्वार के विशिष्ट प्रतिनिधि

एवं कवि विष्णु शर्मा कुमार ने कहा कि राम तो राष्ट्र के मान सम्मान है, राम सब में रमे श्रेष्ठ भगवान है, राम रघुवंश मणि भूप दशरथ तनय , राम परमात्मा प्राण के प्राण है । राम के आदर्श पारिवारिक जीवन, सामाजिक जीवन अनुकरणीय है। आज आवश्यकता है चिंतन चरित्र एवं व्यवहार को पवित्र एवं सद्गुणी बनाया जाए । मौके पर रामचंद्र गुप्ता , जगतपाल पटेल, इंजीनियर बद्री प्रसाद आदि लोग उपस्थित रहे।

शुभारम्भ स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत निकाली गई रैली

विधायक निधि से करछना के चाका, कौंधियारा एवं करछना ब्लॉक के परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की अवस्थापना के कार्यों का शुभारम्भ

स्वतंत्र प्रभात

ब्यूरो प्रयागराज। विधायक करछना पीयूष रंजन निषाद एवं जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ ने मंगलवार को कंपोजिट स्कूल करेहा करछना में विधायक निधि से करछना के चाका, कौंधियारा एवं करछना ब्लॉक के परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास की अवस्थापना के कार्यों का शुभारम्भ किया। स्कूल चलो अभियान के अंतर्गत रैली निकाली गई। स्कूल चलो अभियान की इस मुहिम में क्षेत्र के कई परिषदीय, शासकीय एवं मान्यता प्राप्त विद्यालयों ने अपनी प्रतिभागिता दिखाई। रैली में श्रृंगी ऋषि इंटर कॉलेज घटवा, मदन मोहन मालवीय इंटर कॉलेज करछना, रामराज सिंह इंटर कॉलेज करछना, सुभाष चंद्र इंटर कॉलेज छीटपुर कर्मा, इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज अकोड़ा करछना, बृज मंगल सिंह इंटर कॉलेज मुगारी करछना, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज मुगारी करछना के सभी प्रधानाध्यापक, शिक्षक

शिक्षिकाओं एवं बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रैली में करछना कौंधियारा एवं चाका ब्लाक के प्रतिनिधि शिक्षक शिक्षकों और बच्चों ने भी प्रतिभाग किया। विधायक करछना पीयूष रंजन निषाद ने समग्र शिक्षा उत्तर प्रदेश द्वारा प्रदत्त लर्निंग बाय डूइंग प्रयोगशाला का लोकार्पण भी किया, इसके उपरांत विधायक ने करछना तहसील के अंतर्गत आने वाले तीनों ब्लॉक के चिन्हित विद्यालयों को स्मार्ट क्लास की सुविधा प्रदान करते हुए भविष्य में सभी परिषदीय विद्यालयों को स्मार्ट बनाने की कार्य योजना से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि बच्चे ही देश के भविष्य है, बुनियादी शिक्षा के साथ-साथ तकनीकी शिक्षा का ज्ञान भी आवश्यक है, इसमें स्मार्ट क्लास की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस अवसर पर जिलाधिकारी रविन्द्र कुमार माँदड़ ने अपने उद्बोधन में विधायक करछना के द्वारा स्मार्ट क्लास हेतु व्यवस्था किए जाने के कार्य की सराहना की एवं सभी उपस्थित शिक्षकों और अभिभावकों को उत्कृष्ट शिक्षा के विभिन्न सोपानों से अवगत कराया। जिलाधिकारी ने गर्मी के कारण कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों का समय प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 12:00 तक किए जाने की घोषणा भी की। परिषदीय शिक्षक शिक्षिकाओं ने योजना अनुसार टी एल एम प्रदर्शनी विज्ञान किट, गणित किट, विज्ञान प्रयोगशाला प्रदर्शनी भी लगाई। इस दौरान कंपोजिट स्कूल के सभी स्टाफ का अद्वितीय योगदान रहा एवं विद्यालय की इंचार्ज प्रधानाध्यापिका सुनीता द्विवेदी को जिलाधिकारी ने संयुक्त रूप से सम्मानित किया। बेसिक शिक्षा अधिकारी ने करछना तहसील के सभी निपुण विद्यालयों को भी सम्मानित किया एवं निपुण भारत अभियान में प्रयागराज को प्रदेश में दूसरा स्थान प्राप्त करने पर सभी शिक्षा प्रतिनिधियों को बधाई दी। करछना की स्काउट गाइड टीम ने भी अपना अद्वितीय प्रदर्शन करते हुए गाइड मास्टर पुष्पराज सिंह एवं उनकी टीम में श पूनम वर्मा विद्या पांडे आशा वर्मा मधु जोशी रुकैया रशीद अंसारी गरिमा सिंह कीर्ति मिश्रा काजल जायसवाल किरण सिंह मोनिका श्रीवास्तव एवं सलमा बानो सहित अन्य शिक्षकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। करछना ब्लॉक के विभिन्न परिषदीय विद्यालयों से आए हुए बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया।

जिम्मेदारों की सरपरस्ती में निजी भूखंड स्वामियों को नगर पालिका परिषद संडीला बेंच रही नालों की मिट्टी।

सण्डीला(हरदोई)। भ्रष्टाचार एक ऐसी महामारी है जो नपाप सण्डीला में इस कदर व्याप्त है जिसे कम या समाप्त करने की जगह विभागीय जिम्मेदार स्वयं बढ़ावा देते हुए नजर आ रहे हैं।समाजसेवियों ने आरोप लगाते हुए बताया कि संडीला में नगर पालिका परिषद के अधिकारी और ठेकेदार नालों से मिट्टी निकालकर निजी भूखंडों पर डालकर आसानी से पैसा कमाने की कुटिल योजना में शामिल हैं। इस अवैध गतिविधि की जानकारी होने के बावजूद किसी भी अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की। संपर्क करने पर नपाप ईओ विजेता गुप्ता ने कहा कि उन्हें इस मामले की कोई जानकारी नहीं है, जिससे पूरा शहर भ्रष्टाचार के दलदल में डूबा हुआ है।लोगों के मुताबिक यह देखना वाकई निराशाजनक है कि लगातार शिकायतों के बाद भी अधिकारियों द्वारा कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। संडीला नगर पालिका परिषद में भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों का डर पालिका ईओ पर भी हावी लग रहा है, जिससे कोई भी प्रभावी हस्तक्षेप नहीं हो पा रहा है। यही कारण है कि संडीला में अधिकारी और ठेकेदार भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जबकि संबंधित अधिकारी आंखें मूंदे हुए हैं।समाजसेवियों ने बताया कि यह जरूरी है कि जिला मजिस्ट्रेट हस्तक्षेप करें और नगर पालिका परिषद से भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए संडीला में भ्रष्ट अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

'ट्रम्प का टैरिफश् ईर्ष्या से आया ख्यालए अब दुनिया है बेहाल...!

ट्रम्प के मन में टैरिफ को लेकर आया विचार एकाएक नहीं है। उनके व्यवसाय को जापानियों से मिली चुनौतियों के चलते 1990 के दशक में की घटना है जिससे क्रुध्द ट्रम्प आज पलटवार कर रहे हैं। यह अर्से से उनके मन में पाला हुआ मंसूबा है। वास्तव में ट्रम्प के मन में जापानियों की प्रतिभा को लेकर पनपा ईर्ष्याभाव ही आज उनके टैरिफ की असल वजह है। वो मानते हैं कि जब मुक्त व्यापार अस्तित्व में नहीं था तब जापानए अमेरिका के बाजार में जबरदस्त पैठ बना रहा था। लेकिन अपने यहां व्यापार करना असंभव सा कर दिया था। बस यही टीस बिजनेसमैन ट्रम्प को घर कर गई और उनके मन में एक गांठ बन गई। हालांकि उसी दौर में उन्हें नगदी की जबरदस्त जरूरत हुई और मजबूरन जापान की ओर आस भरी निगाहों से देखने लगे। लेकिन ट्रम्प 1980 के दशक से ही इस बात से बखूबी वाकिफ थे कि मशहूर जापानी निवेशक रॉकफेलर अमेरिकी ब्रांड्स और संपत्तियों के अधिग्रहण का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इससे उनका नजरिया ऐसा बदला जो आज आयात पर टैरिफ के सच के रूप में सामने है। यहीं से उनके दिमाग में अमेरिका के राष्ट्रपति बनने का मंसूबा भी बना और वो लंबी रणनीतियों और विचारों को लोगों से सार्वजनिक मंच पर जाहिर भी करने लगे।

1987 में ट्रम्प की किताब श्ट्रंप. द आर्ट ऑफ द डीलश् में अमेरिकी व्यवसाय पर उनकी विस्तृत सोच के साथ मंशा भी झलकती है। लोकप्रिय द ओपरा शो के होस्ट ओपरा विनफ्रे के साथ भी तभी एक लाइव कार्यक्रम में साफ.साफ कहना कि अमेरिकी विदेश व्यापार नीति को वो कैसे सबसे अलग तरीके से संभालेंगे और इससे अमेरिका के लिए सही कीमत वसूलेंगे उनका रणनीतिक शो था। इतना ही नहीं ट्रम्प ने अपने विचारों को एक खुली चिट्ठी के रूप में अमेरिका के सर्वाधिक लोकप्रिय तीन समाचार पत्रों में भी बतौर विज्ञापन प्रकाशित करवाया जिसमें उनके एक लाख डॉलर खर्च हुए थे। मतलब उनका नजरिया पहले ही साफ हो चुका था। लेकिन यह भूलना चाहिए कि उनकी सोच और वास्तविकता में तब और अब में काफी फर्क है। आज अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वन्दी चीन है न कि जापान। 1990 के दशक के युवा रियल एस्टेट डेवलपर ट्रम्प की सोच आज भी वही है जबकि समय के साथ काफी कुछ बदल गया है। लेकिन ट्रम्प हैं कि मानते नहीं। बतौर राष्ट्रपति और व्यवसायी ऐसी सोच अंतर्राष्ट्रीय हितों के खिलाफ हो सकती है। जैसा कि झलक रहा है इससे अमेरिका में विदेशी व्यापारिक निवेश घटेगा जिसका अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन पर भी असर पड़ेगा।

सौ देशों की अमेरिकी शिडस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफश् वाली सूची में भारत भी शामिल है जिस पर 26 प्रतिशत टैरिफ है जो कई एशियाई देशों की तुलना में कम है। भले ही भारत पर इसका प्रभाव अभी कम पड़े। लेकिन भविष्य को लेकर कोई गारंटी भी तो नहीं कि कब और कितना बढ़ जाएघ् इधर चीन ने भी अमेरिका पर 34 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया है। जिस पर तिलमिलाए ट्रम्प ने 9 अप्रेल तक इसे वापस नहीं लेने पर 50 प्रतिशदत टैरिफ की धमकी दे रहे हैं। अगर अमेरिका अपने हिसाब से चलने की जिद करेगा तो चीन भी आखिर तक लड़ेगा।

इधर ब?लूमबर्ग की हालिया सूची बताती है कि ट्रंप के करीबी मस्क की कुल नेटवर्थ 300 अरब डॉलर के नीचे चली गई है। जनवरी 2025 से अब तक 135 अरब डॉलर यानी करीब 12 लाख करोड़ रुपये का नुकसान उठा चुके हैं। इसी सोमवार को अमेरिकी बाजार में आई गिरावट से मस?क को करीब 40 हजार करोड़ रुपये का नुकसान हुआ जबकि बीते हफ्ते दो दिन में ही मस्क के 31 अरब डॉलर डूब गए। इस तरफ ट्रम्प के अघोषित टैरिफ वार से विश्व में सबसे नुकसान उठाने वालों की सूची में मस?क 6वें क्रम पर आ चुके हैं। कुल मिलाकार आसार अच्छे नहीं है। नए बजट में ग्रामीण विकास के लिए 1ए88ए754 करोड़ तथा किसान कल्याण के लिए बीते बरस की तुलना में 11 प्रतिशत ज्यादा यानी 1ए71 लाख करोड़ रुपयों का बजट में प्रावधान बताता है कि हमारी अपने आर्थिक मोर्चो पर कैसी तैयारी है।भले ही 02 अप्रैल 2025 को ट्रम्प ने अमेरिका का मुक्ति दिवस बता रहे हों। लेकिन जिस तरह से दुनिया भर के शेयर बाजार धराशायी हुएए उससे कुछ अलग ही समझ आ रहा है। ट्रम्प भले ही कहें कि हमारे करदाताओं को 50 से अधिक वर्षों से लूटा जा रहा है। लेकिन रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने वाला आदेश उनकी ईर्ष्याए खीझ और अजीब दूरगामी सोच ही दर्शाता है।

अब अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर यूरोपीय यूनियने के टैरिफ के लिए 9 अप्रैल का इंतजार करना होगाए जिस पर मतदान होना है। यदि यह भी जस का तस जैसे रहा तो आसार और बिगड़ सकते हैं। पहले ही दुनिया भर के शेयर बाजार धड़ाम हो चुके हैं। खुद अमेरिका भी इसी से अछूता नहीं है।

ट्रम्प का अमेरिका में ही विरोध होने लगा है। उन्हे न केवल तानाशाह बल्कि अर्थव्यवस्था को तहस.नहस करने वाला सनकी तक कहा जाने लगा है। सभी 50 राज्यों में 150

संगठनों 1200 से ज्यादा प्रदर्शनों में हजारों का जुटना बताता है कि चिंता कितनी गंभीर है। श्हैंड्स ऑफश् नाम के इस प्रदर्शन में शनिवार को हजारों लोग जुटे। 2017 में महिला मार्च और 2020 में ब्लैक लाइव्स आन्दोलन के बाद ट्रंप का ऐसा भारी विरोध हो रहा है। असल में एलन मस्क का दखल भी अमरीकियों को पसंद नहीं आ रहा है। उन पर नौकरी में छंटनियों के मंसूबों सहित सत्ता हथियाने जैसे गंभीर आरोप लग रहे हैं। इधर भारत और खुद अमरीका सहित दुनिया भर के शेयर बाजारों में आज खुलते ही जबरदस्त तो कहीं ऐतिहासिक गिरावट देखी जा रही है। निश्चित रूप से शुभ संकेत नहीं है

व्यावसायिक हितों और तमाम दूसरे मामलों में सतर्क दुनिया ने एकजुट होकर ट्रम्प को जवाब देना शुरू कर दिया है जिससे वैश्विक ट्रेड वार की आशंका बढ़ गई है। काश ऐसा नहीं होता और ट्रम्प समझदारी और विवेक से काम लेते। दुनिया में कम से कम खुशहाल इंसानियत के लिए तो सौदेबाजी से बचा जाए। लेकिन ट्रम्प नहीं माने और बदली हुई परिस्थितियों में बाकी सभी एकजुट हो आपदा में अवसर तलाशने लगे तो कहीं अमेरिका ही हासिए पर न चला जाएघ् अच्छा होता कि इतना तो ट्रम्प समझ पाते!

ऋतुपर्ण दवे

वर्तमान की हार, भविष्य का शोक, नशे की चपेट में भारत का युवा मन

भारत को जब दुनिया का सबसे युवा देश कहकर संबोधित किया जाता है, तो यह केवल आंकड़ों की बात नहीं होती, यह उस उम्मीद की भी अभिव्यक्ति है जो करोड़ों सपनों में पल रही होती है। परंतु इन दिनों यह वाक्य किसी गौरव का नहीं, बल्कि एक गंभीर संकट का संकेत बनता जा रहा है। क्योंकि वही युवा, जिन्हें देश का भविष्य कहा जाता है, आज एक अदृश्य मगर घातक जहर के गिरफ्त में आते जा रहे हैं नशे की लत में फँसकर। यह कोई अचानक फैला संकट नहीं है। यह एक धीमी, भीतर से खाती हुई महामारी है, जो वर्षों से हमारे आसपास पनप रही थी और अब उसने एक सार्वजनिक त्रासदी का रूप ले लिया है। यह संकट न केवल शरीरों को नष्ट कर रहा है, बल्कि आत्माओं, परिवारों, समुदायों और पूरे समाज की चेतना को भी गलाने लगा है। यह एक ऐसी धीमी आत्महत्या है, जो हर वर्ष लाखों युवाओं को अपने घेरे में ले रही है। राष्ट्रीय संस्थानों की रिपोर्टें यह बताती हैं कि भारत में मादक पदार्थों के नियमित सेवन करने वालों की संख्या करोड़ों में है, और उनमें से बड़ी संख्या युवा वर्ग से आती है। ये आंकड़े, दरअसल आँकड़े नहीं विलाप हैं, चीखें हैं, और टूटते हुए भविष्य की वे दरारें हैं जिनमें एक समाज की बुनियाद धँसती जा रही है। हम यह त्रासदी अब सिर्फ पंजाब की सीमा में नहीं देख रहे। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, हिमाचल, झारखंड और पूर्वोत्तर राज्यों तक फैल चुकी है। नशा अब शहरी समस्या नहीं रहा, यह गाँवों के खेतों में, कस्बों की गलियों में, स्कूलों और मज़दूर बस्तियों में अपनी जड़ें जमा चुका है। भारत की भौगोलिक स्थिति भी इस आग में घी डाल रही है। गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्राएंगल जैसे विश्व के सबसे बड़े ड्रग उत्पादन क्षेत्रों के बीच स्थित भारत अब केवल ट्रांजिट पॉइंट नहीं, एक विशाल उपभोक्ता बाज़ार बन गया है। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि नशा अब अपराध नहीं, एक सांस्कृतिक सामान्यता बनता जा रहा है। 'हाई' होना अब शर्म की नहीं, शान की बात मानी जाती है। सोशल मीडिया पर नशे की स्थिति को उत्सव की तरह प्रदर्शित किया जाता है। रैप गीतों में गांजा और व्हिस्की के जिक्र को रचनात्मकता कहा जाता है, फिल्मों में शराब को प्रेम और विरह का प्रतीक बनाकर प्रस्तुत किया जाता है। यह सब एक सामूहिक सम्मोहन का निर्माण करता है, जिसमें युवा यह मान बैठता है कि भीतर की टूटन से उबरने का सबसे आसान और स्वीकार्य रास्ता आत्मविनाश है।इस त्रासदी की जड़ें और गहरी हैं। भारत का युवा मानसिक स्वास्थ्य के एक अदृश्य युद्धक्षेत्र में संघर्ष कर रहा है। वह अकेला है, दबाव में है, और बार-बार असफलताओं के बोझ से टूटा हुआ है। वह एक ऐसा समाज देखता है जहाँ माता-पिता उसे नौकरी दिलवाने की चिंता तो करते हैं, लेकिन उसकी मनोवैज्ञानिक जरूरतों को या तो अनदेखा कर देते हैं या अनुशासनहीनता का नाम दे देते हैं। शिक्षण संस्थान उसके व्यवहार को अनुशासन की समस्या मानकर सतही उपचार करते हैं। और उसके मित्र उसे विचलन के लिए उपहासित करते हैं। इस सामाजिक संवादहीनता के बीच जब वह अपने भीतर के दुःख और असुरक्षा से लड़ नहीं पाता, तो वह नशे की तरफ मुड़ जाता है। क्योंकि वही एकमात्र ऐसा सहारा है जो उसे बिना प्रश्न किए, बिना जज किए, उसकी बेचैनी को सुन्न करने का अवसर देता है। लेकिन यह सवाल केवल युवाओं का नहीं है। यह सवाल हमारे पूरे समाज का है उस समाज का जो अब सुनने की शक्ति खो चुका है। हमारे पास संचार के सबसे आधुनिक माध्यम हैं, लेकिन हमारे बीच संवाद नहीं है। हम हजारों लोगों से जुड़े हैं, लेकिन किसी एक को भी अपना दुःख नहीं कह सकते। यह चुप्पी ही वह खालीपन है, जो नशे की आदत को जगह देता है। और जब कोई युवा टूटता है, तो हम उसे अपराधी समझने लगते हैं, जबकि वह दरअसल एक अनसुनी चीख का पात्र होता है। राजनीतिक स्तर पर कई योजनाएँ और नशा मुक्ति अभियान चले हैं, पर वे अधिकतर औपचारिकता या प्रचार तक सीमित रह गए हैं। समस्या की गंभीरता को देखते हुए अब केवल सतही उपायों से काम नहीं चलेगा। एक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो समाज की संरचना में हस्तक्षेप करे, और रोकथाम के साथ-साथ पुनर्रचना की दिशा में भी सार्थक कदम उठाए। नशा मुक्ति केंद्रों को केवल 'सुधारगृह'नहीं, बल्कि सहानुभूति के केंद्र के रूप में बदला जाना चाहिए जहाँ काउंसलिंग, रचनात्मक गतिविधियाँ और मानवीय स्पर्श प्राथमिकता हो। साथ ही, हमारी शिक्षा प्रणाली में केवल करियर निर्माण पर नहीं, जीवन कौशल, भावनात्मक बौद्धिकता और आत्म-सम्वेदनशीलता पर भी ज़ोर दिया जाना चाहिए।

परिवारों की भूमिका भी इस प्रक्रिया में केंद्रीय होनी चाहिए। माता-पिता को यह समझना होगा कि अनुशासन ही नहीं, सहचरता भी जरूरी है। उनके लिए भी संवाद के नए ढांचे बनाए जाने चाहिए जहाँ वे अपने बच्चों के साथ बैठकर सिर्फ बातें करें। उनकी भावनाओं, उनके डर, और उनके सपनों के बारे में। एक सामूहिक चेतना का निर्माण करना होगा जो यह समझे कि नशा केवल एक व्यक्ति की समस्या नहीं, बल्कि एक टूटते समाज का लक्षण है। लेकिन इस अंधकार के बीच आशा के द्वार भी हैं। युवाओं के भीतर ऊर्जा है। असीम, अदम्य और सृजनशील ऊर्जा। अगर इस ऊर्जा को सही दिशा दी जाए, तो वही युवा जो आज नशे की गिरफ्त में है, कल किसी गाँव का शिक्षक, किसी कविता मंच का वक्ता या किसी थिएटर का अभिनेता हो सकता है। कला, साहित्य, संगीत, खेल ये केवल मनोरंजन के साधन नहीं, बल्कि उपचार के माध्यम हैं।

युवाओं को अपने अनुभवों को अभिव्यक्ति देने के मंच चाहिए, ऐसे मंच जहाँ वे टूटन को रचना में बदल सकें। सरकार को चाहिए कि वह हर जिले में ऐसे रचनात्मकता केंद्र बनाए, जहाँ युवा मुफ्त में अभिनय, लेखन, पत्रकारिता, फिल्म निर्माण, सामाजिक सेवा और संवाद-चर्चा में भाग ले सकें। यह केवल क्रियाकलाप नहीं, बल्कि एक वैकल्पिक जीवन-दृष्टि है, जो नशे के विकल्प के रूप में खड़ी हो सकती है। यह समय केवल सरकारों की परीक्षा का नहीं, समाज की चेतना की भी परीक्षा का है। क्या हम वह समाज बनेंगे जो अपने युवाओं को टूटते हुए चुपचाप देखता रहेगा? या वह समाज बनेंगे जो हर टूटती आवाज़ के साथ खड़ा होता है उसे सुनता है, समझता है और थाम लेता है? हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि युवा केवल देश का भविष्य नहीं, वर्तमान भी हैं। और अगर हमने उनके वर्तमान को अंधकार में डुबो दिया, तो भविष्य हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। अब समय है मौन तोड़ने का, हाथ बढ़ाने का और एक ऐसा भारत गढ़ने का, जहाँ हर युवा को यह महसूस हो कि उसका जीवन मूल्यवान है अर्थवान है।

स्वागत योग्य एवं अनुकरणीय है शराबबन्दी

मध्य प्रदेश सरकार ने धार्मिक महत्व के 19 नगरों एवं ग्राम पंचायतों में एक अप्रैल से शराब बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगा दिया हैद्य प्रदेश के मुख्यमन्त्री मोहन यादव के अनुसार उज्जैनए ओंकारेश्वरए महेश्वरए मण्डलेश्वरए ओरछाए मैहरए चित्रकूटए दतियाए पन्नाए मण्डलाए मुलताईए मंदसौर और अमर कण्टक की नगरीय सीमा में शराब नहीं बिकेगीद्य इसके अलावा सलकनपुरए कुण्डलपुरए बांदकपुरए बरमानकलांए बरमानखुर्द एंव लिंग ग्राम पञ्चायत सीमा में भी शराब की सभी दुकाने और बार बन्द करवाने का आदेश दिया गया हैद्य प्रदेश सरकार का यह कदम स्वागत योग्य एवं अनुकरणीय हैद्य अच्छा होता यदि यह बन्दी पूरे प्रदेश में लागू होतीद्य मध्य प्रदेश सरकार का यह कदम पहला और नया नहीं हैद्य बिहारए गुजरातए मिजोरम और नागालैण्ड में पहले से ही शराब बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगा हुआ हैद्य शराब पर प्रतिबन्ध लगाने वाला गुजरात इस देश का पहला राज्य हैद्य जहाँ उसके जन्म वर्ष 1960 से ही शराब का निर्माणए बिक्री और सेवन पूर्णतया प्रतिबन्धित हैद्य जबकि बिहार में अप्रैल 2016 में शराब बन्दी कानून लागू हुआ थाद्य हालाकि प्रतिबन्ध के बावजूद बिहारियों की एक बड़ी आबादी मदिरा पान करती हैद्य केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय द्वारा कराये गये सर्वे में बिहार के 17 प्रतिशत लोग मदिरासेवी पाये गयेद्य परन्तु इससे शराब बिक्री पर प्रतिबन्ध लगाना निरर्थक नहीं हो जाताद्य उपरोक्त राज्यों में प्रतिबन्ध लगा होने के कारण ही भारत में शराब पीने वालों की संख्या में काफी हद तक कमी आई हैद्य केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय की तरफ से हाल ही जारी किये गये आंकड़ों के अनुसार भारत के 22.4 प्रतिशत पुरुष शराब का सेवन करते हैंद्य जबकि 2015.16 में जारी आंकड़ों में यह प्रतिशत 29.2 था। वहीँ शराब पीने वाली महिलाओं का प्रतिशत 1.2 से घटकर 0.7 हो गया हैद्य जिन राज्यों में शराब बिक्री पर प्रतिबन्ध नहीं है वे राष्ट्रीय औसत से बहुत आगे हैंद्य जिसमें गोवा के 59.1 प्रतिशतए अरुणाचल प्रदेश के 56.6 प्रतिशतए तेलंगाना के 50 प्रतिशतए झारखण्ड के 40.4 प्रतिशतए ओडिशा के 38.4 प्रतिशतए सिक्किम के 36.3 प्रतिशतए छत्तीसगढ़ के 35.5 प्रतिशतए उत्तराखण्ड के 32ए1 प्रतिशतए आन्ध्र प्रदेश के 31.2 प्रतिशतए दिल्ली के 27.9 प्रतिशतए पंजाब के 27ए5 प्रतिशतए असम के 26.5 प्रतिशतए केरल के 26 प्रतिशत तथा पश्चिम बंगाल के 25.7 प्रतिशत पुरुष मदिरा पान करते हैंद्य इसी तरह प्रदेश वार यदि महिलाओं की बात करें तो सबसे अधिक असम में 26.3 प्रतिशत तथा मेघालय में 8.7 प्रतिशत स्त्रियाँ शराब का सेवन करती हैंद्य अरुणाचल प्रदेश में शराब पीने वाली महिलाओं का आंकड़ा पहले 33.6 था। जो अब घटकर मात्र 3.3 प्रतिशत रह गया हैद्य क्रिसल नामक एजेंसी द्वारा 2020 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार शराब की खपत में पहले नम्बर पर छत्तीसगढ़ और दूसरे पर त्रिपुरा राज्य है। तीसरे नम्बर पर आन्ध्र प्रदेशए चौथे पर पंजाबए पांचवें पर अरुणाचल प्रदेश है। जबकि जम्मू.कश्मीरए राजस्थानए महाराष्ट्र और लक्षद्वीप में सबसे कम शराब पी जाती है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की 23.8 प्रतिशत आबादी शराब का सेवन करती हैद्य जिसका आयु वर्ग 10 वर्ष से 75 वर्ष के बीच हैद्य गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश की कुल आबादी लगभग 24 करोड़ है। जिसका 23.8 प्रतिशत अर्थात लगभग 6 करोड़ लोग शराबी हैं। जो एक गम्भीर चिन्ता का विषय है।

मदिरा व्यापार का प्रमुख पहलू सरकारों को इससे मिलने वाला भारी भरकम राजस्व है। इसीलिए अन्य सभी प्रदेश सरकारें बिहारए गुजरातए मिजोरम और नागालैण्ड की तरह शराब बन्दी का साहस नहीं जुटा पा रही हैंद्य उत्तर प्रदेश के आबकारी विभाग ने वर्ष 2024.25 में 52297.08 करोड़ रूपये का राजस्व अर्जित किया है और चालू वित्त वर्ष में 55 हजार करोड़ रूपये से अधिक का लक्ष्य रखा है। पंजाब सरकार को 10743.72 करोड़ का राजस्व बीते वित्तीय वर्ष में प्राप्त हुआद्य जबकि चालू वित्त वर्ष का लक्ष्य 11020 करोड़ रूपये है। वहीँ दिल्ली की प्रदेश सरकार ने बीते वित्तीय वर्ष में 5068.92 करोड़ का राजस्व शराब से प्राप्त कियाद्य छत्तीसगढ़ सरकार की वर्ष 2023.24 में शराब बिक्री से 8 हजार करोड़ रूपये से अधिक कमाई हुई थी। इस तरह जिन राज्यों में शराब की बिक्री प्रतिबन्धित नहीं है वहां की सरकारें शराब से जबर्दस्त कमाई कर रही हैंद्य कोरोना काल में लॉक डाउन के चलते खाली होते खजाने को भरने के लिए सरकार को शराब की दुकाने खोलनी पड़ी थीं।

शराब की बिक्री सरकारों का राजस्व बढ़ाने में भले ही महती भूमिका निभा रही हो। परन्तु इसका सेवन किसी भी दृष्टि से हितकारी नहीं हैद्य समाज के आर्थिक और नैतिक पतन के लिए शराब ही सर्वाधिक जिम्मेदार हैद्य गृह कलह और घरेलू हिंसा के बढ़ते मामलों के मूल में शराब ही दिखाई देती है। 31 मार्च को हमीरपुर जनपद के मुस्करा नामक कस्बे में शराबी पति की प्रताड़ना और गृह कलह से आजिज आकर पत्नी ने चाकू से गला रेतकर उसकी हत्या कर दी थी। नशेबाजी के चलते गाँवोंए कस्बों तथा शहरों की गलियों में

विवादए मारपीट और हत्या तक के समाचार आये दिन प्राप्त होते हैंद्य दरकते रिश्तेए टूटते परिवारए बिखरता सामाजिक ताना.बानाए छेड़छाड़ और बलात्कार के बढ़ते मामलों के लिए शराब का नशा ही प्रथम दृष्ट्या दोषी है। हर दिन होती मार्ग दुर्घटनाओं के ज्यादातर मामले शराब पीकर वाहन चलाने के कारण ही होते हैं। जबकि शराब पीकर वाहन चलाना कानूनी जुर्म हैद्य फिर भी कोई मानने को तैयार नहीं हैद्य क्योंकि बाजार में शराब उपलब्ध हैद्य बिहार जैसे राज्यों में यदि शराब बिक्री प्रतिबन्धित है तो वहां अवैध रूप से शराब बिक रही है। अन्यथा 17 प्रतिशत बिहारी शराबी न होतेद्य कोई कितने भी तर्क क्यों न दे परन्तु शराब का सेवन किसी भी दृष्टि से लाभदायक नहीं है। आज गुजरात के विकास मॉडल की चर्चा हर जगह होती है। सभी प्रदेश सरकारें उसका अनुकरण करना चाहती हैं। परन्तु वहां की शराबबन्दी नीति की चर्चा कोई नहीं करता। गुजरात राज्य यदि प्रगति के नित नये सोपान चढ़ रहा है तो उसके मूल में कहीं न कहीं वहां के लोगों का शराब मुक्त जीवन हैद्य उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्य सरकारों को इस दिशा में गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिए।

डॉ.दीपकुमार शुक्ल

संपादकीय

स्वतंत्रता का अतिक्रमण सामाजिक दायित्वों का हनन, कर्तव्यों से विमुख न हों।

वाल्टेयर जी ने इस संदर्भ में ठीक ही कहा है कि अधिकार बढ़ने के साथ-साथ समानुपातिक रूप से उत्तरदायित्व भी धीरे-धीरे बढ़ जाता है।

वर्तमान के इस दौर में जब देश में लोकतंत्र अपनी अस्मिता बचाने की जद्दोजहद में है वहां समाज का हर नागरिक अपने लिए अधिक से अधिक अधिकारों की इच्छा रखता है ताकि पूरी स्वतंत्रता का उपभोग कर सके। इसी के फलस्वरूप हर रोज अधिकारों की बढ़ती मांग और कर्तव्य की अवहेलना से समाज वातावरण में असंतुलन बढ़ता जा रहा है। वॉलटेयर जी ने इस संदर्भ में ठीक ही कहा है कि अधिकार बढ़ने के साथ-साथ समानुपातिक रूप से उत्तरदायित्व भी धीरे-धीरे बढ़ जाता है हमें अपने अधिकारों के साथ अपनी जिम्मेदारियों का भी ज्ञान बोध होना जरूरी है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि अधिकार तथा उत्तरदायित्व समानुपातिक है और समाज में हर व्यक्ति समुदाय के साथ संग संग चलते हैं। ऐसा कुछ है कि स्वतंत्रता और खुलेपन के संग उत्तरदायित्व जी जीवन की यात्रा में सहयात्री है। स्वतंत्रता या खुलेपन का अतिक्रमण किसी व्यक्ति के दायित्वों का हनन है हम जहां जिस ग्राम नगर अथवा देश में रहते हैं वहां पर यह सुनिश्चित है कि अधिकार एवं जिम्मेदारी हमारे साथ साथ विचरण करते दिखाई देते हैं। भारतीय संविधान में अधिकारों की मीमांसा करते हुए यह मूल रूप से माना गया है कि यहां देश में मूल अधिकारों को महत्व इसीलिए दिया जाता है की भारतीय जनमानस का बड़ा प्रतिशत अशिक्षित है अतः संविधान अशिक्षित व्यक्तियों के लिए ज्यादा से ज्यादा स्वतंत्रता और समानता प्रदाय कर सके ताकि फिर कोई समाज या राज्य उसका हनन न कर सके, दूसरी तरफ यदि कर्तव्य की बात करें तो सदैव यह हिदायत दी जाती रही है कि भारत की जनता अधिक मात्रा में अशिक्षित हैं अतः उन्हें अपने दायित्वों का ज्ञान तथा अनुभूति नहीं होगी और दायित्व और कर्तव्यों के बीच बड़ी लक्ष्मण रेखा खिच गई है।

व्यक्ति और समाज जैसे जैसे विकसित होता गया है और आधुनिकता के इस दौर में नागरिकों की अधिकारों की मांग बढ़ती जा रही है। हमें अधिकार धीरे-धीरे मिल भी रहे जिस तरह माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के अधिकार को मूल अधिकार की श्रृंखला में रखकर नागरिकों की स्वतंत्रता को सुरक्षित बनाने का प्रयास किया है। अब ऐसे में हमारा दायित्व बनता है कि हम अपनी निजता के अधिकार को अपने पास रखते हुए दूसरे की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नुकसान ना पहुंचाएं या उसकी स्वतंत्रता पर अतिक्रमण न करें, जिससे जिम्मेदारी और कर्तव्य बोध संग संग चलते रहे और सामाजिक परिवेश का कर्तव्य तथा अधिकार के बोध में सामंजस्य बना रहे। हम अपने व्यक्तिगत हित के कारण यह तथ्य विस्मित कर देते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक राज्य के नागरिक हैं और हमें लोक कल्याण की अवधारणा को मूर्त रूप देना है जिससे कि राष्ट्र का विकास संभावित है। हम अपने आधुनिकता के चलते अपने दायित्व और मूल्यों के प्रति असावधान होते जा रहे हैं भारतीय समाज में बदलते समय के साथ नागरिक नैतिक मूल्यों की परवाह किए बगैर अपनी स्वच्छंदता एवं शक्ति के बल पर मनमानी तथा भ्रष्टाचार निरंकुशता को सर्वोपरि बनाने में लगे हुए है। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत देश के आम नागरिकों के द्वारा राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधियों को विधिवत चुनकर संसद तथा विधान भवन भेजती है ताकि राज्य और देश का कल्याण हो सके किंतु अपने अधिकारों के प्रति उत्साहित यह राजनेता अपने मूलभूत कर्तव्य को भूलकर जनता का शोषण करने में लीन हो गए हैं और अधिकार संपन्न होकर निरंकुशता की श्रेणी में आकर बैठ गए हैं। इन जनप्रतिनिधियों ने अपने अधिकार तथा उत्तरदायित्व में तालमेल न बिठा कर शासन की व्यवस्था को बिगाड़ कर रखा है।

अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने लिखा है कि जिस देश की आम जनता झोपड़पट्टी में रह रही हो उस देश के शासक प्रशासक को महलों में रहने का कोई अधिकार नहीं बनता है। यह बात उन्होंने बहुत पहले कही थी पर यह आज भी अत्यंत प्रासंगिक तथा समीचीन है। वर्तमान में देश में यह बात तो एकदम स्पष्ट है कि हमें अपने अधिकारों को तब भली-भांति ज्ञान व बोध है किंतु उत्तरदायित्व के प्रति हम जानबूझकर अनजान बने हुए हैं यह देश के विकास के लिए उचित नहीं है इससे देश के विकास में बाधा होती है। अधिकारों तथा उत्तरदायित्व के संदर्भ में कई समितियों ने बड़ी ही नकारात्मक अनुशंसा प्रस्तुत की है जिसमें इस बात का हवाला है कि राजनीति तथा प्रशासन में सब तरफ लालफीताशाही, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद फैला हुआ है क्योंकि हमारे राजनेता शासक प्रशासक अपने अधिकारों का तो समुचित प्रयोग करते हैं किंतु उत्तरदायित्व के मामले में अपने आप को अनभिज्ञ बताते हुए जनता के सामने हाथ खड़े करके निरीह बने रहते हैं।

सरकारी सुविधाओं का उपयोग करना तो हमारा अधिकार है पर उसका रखरखाव और उससे साफ सुथरा रखना हमारा दायित्व भी है किंतु हम अपने दायित्व के प्रति आंखें बंद कर अधिकारों के लिए अंधी दौड़ में शामिल हो चुके हैं। एक संकट जैसे कि पर्यावरण संकट किसी व्यक्ति समाज और राष्ट्र के लिए नहीं है यह वैश्विक समस्या है और यदि हम इसके प्रति सजग नहीं हुए तो 1 दिन संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था पृथ्वी धरा नष्ट हो जाएगी और मनुष्य सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए पानी को तरसने लगेगा। यह हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है कि हम सत्य निष्ठा के साथ सदाचारी बनकर नैतिकता को अपने व्यवहार में उतार कर अपने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा कर अपने अधिकारों के साथ मूल दायित्व को भी उतनी ही गंभीरता से उपयोग में लाएं जिससे व्यक्ति समाज और राष्ट्रहित हो सके।

संजीव ठाकुर

गाजी से लड़ना आसान, मंहगाई से लड़ना मुश्किल

दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता प्रयागराज में मसूद गाजी से तो लड़ सकते हैं लेकिन महंगाई से लड़ना उनके बूते की बात नहीं है। देश में मोदीजी के राज में महंगाई बिना पदचाप के बढ़ रही है लेकिन एक देवतुल्य कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जो अपना भगवा ध्वज लेकर इस मंहगाई पर चढ़ाई कर दे। प्रयागराज में भगवा लेकर मसूद गाजी की दरगाह पर चढ़ने वाले लगता है कागजी शेर हैं।

केंद्र की सरकार देश में अलग-अलग मुद्दों पर एक साथ काम कर रही है। एक तरफ सरकार देश के मुसलमानों से लड़ रही है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस से। तीसरी तरफ ममता बनर्जी से तो चौथी तरफ स्टालिन से ,लेकिन महंगाई से लड़ने की कूबत केंद्र सरकार में नहीं है। उलटे सरकार ने बीती रात अचानक बिना कोई वजह बताये रसोई गैस के सिलेंडर पर 50 रूपये और पेट्रोल-डीजल पर प्रति लीटर 2 रूपये का उत्पादन शुल्क बढ़ा दिया। सरकार का दावा है कि इससे पेट्रोल और डीजल के खुदरा दाम नहीं बढ़ेंगे। सवाल ये है कि यदि खुदरा दाम नहीं बढ़ेंगे तो ये बढ़ा हुआ उत्पादन शुल्क आखिर सरकार किस्से वसूल करेगी।?

मैंने देश में अनेक दलों की सरकारें और अनेक दलों को विपक्ष में बैठे देखा है ,लेकिन ये पहली ऐसी सरकार है जो सीना ठोंककर महंगाई को बढ़ा रही है और कह रही है कि इससे कुछ नहीं होगा। ये उसी पार्टी की सरकार है जो अतीत में पेट्रोल-डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाये जाने पर न सिर्फ जार-जार रोती थी बल्कि सड़क से संसद तक खाली सिलेंडर लेकर,बैलगाड़ियों पर बैठकर विरोध प्रदर्शन किया करती थी। लेकिन पिछले एक दशक ने इस सरकार ने अपने कार्यकर्ताओं कि साथ ही जनता की प्रतिकार की क्षमता को छीन लिया है। समूचे विपक्ष को कुंद बना दिया है। अब न सत्ता पक्ष के लिए महंगाई मुद्दा है और न विपक्ष के लिए। जनता के लिए भी मंहगाई मुद्दा नहीं, एक मजबूरी बन चुकी है ,इसलिए उसे अब सड़कों पर उतरने में लज्जा आती है। ऐसी संकोची जनता का अभिनंदन किया जाना चाहिए।

प्रयागराज के सिकंदरा में सैयद सालार मसूद ग़ाज़ी की दरगाह है। मैंने ये दरगाह देखी है। सिकंदरा स्थित इस दरगाह में पाँच मज़ारें हैं, जहाँ पर दोनों धर्मों के लोग जाते हैं यहीं पर महाराजा सुहेलदेव सुरक्षा सम्मान मंच के कार्यकर्ताओं ने रामनवमी के दिन भगवा झंडा फहरा दिया और पुलिस देखती रह गयी। उत्तर प्रदेश की पुलिस ऐसे तमाशों को देखने के लिए ही बनी है। जाहिर है की दरगाह पर भगवा ध्वजारोहण से तनाव पैदा हुआ लेकिन पुलिस का कहना है कि स्थिति शांतिपूर्ण है।

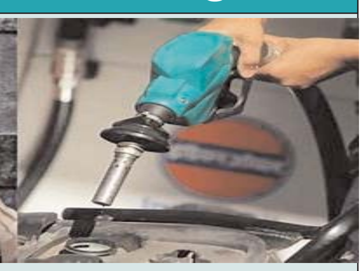

प्रयागराज में गंगानगर के डीसीपी कुलदीप सिंह गुनावत ने बताया, यहाँ कुछ युवकों ने धार्मिक झंडा लहराकर नारेबाज़ी की. इनको मौक़े पर मौजूद पुलिस ने रोका. इस घटना की जाँच की जा रही है। इस मामले में महाराजा सुहेलदेव सम्मान सुरक्षा मंच के अध्यक्ष मनेंद्र प्रताप सिंह को हिरासत में लिया गया है।

लेकिन हैरानी होती है कि गाजी मसूद की दरगाह होया औरंगजेब का मकबरा को लेकर परेशान देशवासी एक बार भी पेट्रोल और डीजल के साथ ही रसोई गैस की कीमतें बढ़ाये जाने से परेशान नहीं होते। उन्हें अपनी ही सरकार पर गुस्सा नहीं आता। आये भी कैसे ? सरकार ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हाथों में भगवा थमाकर उन्हें दूसरे कामों में लगा दिया है। बेचारे हिन्दू , बहुसंख्यक हिन्दू कार्यकर्ता भूल गए हैं कि सरकार उन्हें मूर्ख बना रही है। उनसे बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता उखाड़ने के लिए उन्हें भालू और वानर सेना में भर्ती करा दिया गया है। उन्हें स्टालिन को उखाड़ने की जिम्मेदारी दी गयी है। मंहगाई सरकार के लिए कोई मुद्दा है ही नहीं।

हम हिन्दुओं से भले तो अमेरिका के ईसाई हैं जो अपनी सरकार के गलत फैसलों के खिलाफ सड़कों पर हैं। उनके हाथों में सलीब नहीं है। वे अपने नेताओं की तस्वीरों पर जूते-चप्पल चला रहे हैं उनके ऊपर ईसाइयत को बचाने की नहीं बल्कि देश को मंहगाई और मंदी से बचाने की जिम्मेदारी है। अमेरिका की जनता किसी पोंगापंथ का शिकार नहीं है, हालाँकि अमेरिका में भी वो सब हुआ जो हमारे प्यारे हिंदुस्तान में हो रहा है। अमेरिका की जनता को 'अमेरिका फर्स्ट' का नारा दिया गया था ,लेकिन किया गया उलटा। टैरिफ बढ़कर अमेरिका की सरकार ने आधी से ज्यादा दुनिया को अपना दुश्मन बना लिया। अमेरिका के शेयर बाजार औंधे पड़े है। बेरोजगारी अचानक बढ़ गयी है। धड़ाधड़ छंटनी हो रही है। किन्तु इस सबका विरोध भी हो रहा है। सरकार पर दबाब बनाया जा रहा है।

मंहगाई ने देश की उन करोड़ों लाड़ली बहनों को संकट में डाल दिया है जो बामुश्किल अपनी रसोई की आग ज़िंदा रखे हुए थीं। अब आम महिलाओं के साथ ही उन महिलाओं को भी रसोई गैस की बढ़ी कीमत देना पड़ेगी जिन्हें उज्ज्वला योजना के तहत रियायती सिलेंडर मिलता था। बाजार में इस्तेमाल के लिए जाने वाला सिलेंडर तो लगातार मंहगा होता ही जा रहा है। उसका बोझ भी परोक्ष रूप से आपके ऊपर ही पड़ता है । आप जिस खोमचे से समोसा 10 रुपया देकर खाते थे अब उसकी दाम बढ़ते -बढ़ते 20 रुपया हो चुके हैं।हमारे शहर ग्वालियर में तो समोसा 25 रूपये का बिक रहा है। डीजल के दाम पढ़े तो पहले से मुसीबत के मारे किसान की कमर टूटने वाली है। किसान की कमर टूटेगी तो क्या आम आदमी अपनी कमर बचा पायेगा?

हमारी सरकार इलेक्ट्रानिक सुरक्षा प्रणाली के इस्तेमाल से देश की सीमाओं की सुरक्षा करने का दावा तो करती है लेकिन मंहगाई से जूझने का उसके पास कोई प्लान नहीं है। हमारी सरकार को फ़िक्र बिहार विधानसभा चुनाव जीतने की है । वक्फ बोर्ड क़ानून में संशोधन के बाद वक्फ की सम्पत्ति हड़पने की है। सरकार के मुकाबले विपक्ष और खासकर कांग्रेस को चिंता गुजरात जीतने की है। भारत जोड़ो यात्रा करने वाली कांग्रेस महंगाई के मुद्दे पर सड़कों से नदारद दिखाई दे रही है। कांग्रेस के पास भाजपा और संघ के कार्यकर्ताओं जैसा जोश है ही नहीं। इसलिए बैशाखियों की सरकार मनमानी पर आमादा है।

पेट्रोल और डीजल पर उत्पादन शुल्क बढ़कर कितना कमाएगी सरकार ये हमें नहीं बताया गया ,लेकिन शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में सरकार ने ऑल इण्डिया तृण मूल कांग्रेस की सांसद माला रॉय को बताया था कि सरकार पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क के रूप में 27.90 रुपये लीटर और डीजल पर प्रति लीटर 21.80 रुपये की आय होती है। अब सरकार अपनी आय तो बढ़ा रही है लेकिन जनता की कमर तोड़ने पर आमादा है। सरकार का कहना है कि उसे जो आमदनी होगी वो तेल कमापनियों को मिलने वाले मार्जिन से होगी,आम आदमी पर इसका कोई असर नहीं पडेगा। लेकिन ये झूठ है। तेल कंपनियां अपने मार्जिन में से सरकार का खजाना क्यों भरने लगीं ? वे तो जनता की जेब पर ही डाका डालेंगी।

राकेश अचल

मुद्रक, प्रकाशक एवं सम्पादक रवि कुमार अवस्थी द्वारा सुशीला स्टेडी बेल एकेडमी 117-मोहल्ला विजय लक्ष्मी नगर परगना खैराबाद तहसील व जनपद -सीतापुर से प्रकाशित तथा महावीर आफसेट 28, हीवेट रोड लखनऊ से मुद्रित। सम्पादक रवि कुमार अवस्थी समाचार पत्र में छपे समस्त समाचार संवाददाताओं के अपने श्रोत एवं संकलन हैं, जिनसे सम्पादक का सहमत होना आवश्यक नहीं है। **नोटः**-उपरोक्त सभी पद अवैतनिक एवं स्वयंसेवी हैं तथा समाचार पत्र से सम्बंधित सारे विवादो का न्याय क्षेत्र सीतापुर होगा। R.N.I NO. UPHIN/2012/43078 मो0 नं0 -9511151254,E-Mail :- news@swatantraprabhat .com

संक्षिप्त खबरें

करियातपुर में रामनवमी शांतिपूर्ण संपन्न, जय श्री राम के नारों से गूंजा क्षेत्र

बरही, झारखंड। बरही प्रखंड के अंतर्गत करियातपुर में रामनवमी पूजा शांतिपूर्ण संपन्न हो गई जहां करियातपुर, दुलमाहाँ, कोरियाडीह, धनवार, लखना, पिपरा घोघर में संयुक्त रुप से अपने जुलूस झांकी के साथ शोभायात्रा निकालते हुए करियातपुर के मैदान में सभी राम भक्त जुटे। वही अपने पारंपरिक हथियार के साथ अपने खेल प्रदर्शन का जौहर दिखाते हुए दिखे। प्रशासन के द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के प्रबंध किए गए थे। वहीं श्रद्धालुओं के लिए भवानी केबिनेट के द्वारा शरबत का प्रावधान किया गया था। गौरतलब है कि करियातपुर रामनवमी महासमिति के द्वारा मेले का आयोजन किया गया था जिसकी अध्यक्षता प्रदीप केसरी सचिव सागर चंद्रवंशी कोषाध्यक्ष विनोद यादव, उपाध्यक्ष सुनील केसरी, रामकुमार दास, उपसचिव राजेश शर्मा, उपकोषाध्यक्ष संतोष प्रजापति व संरक्षक के रूप में करियातपुर मुखिया मनोज कुमार, दुलमाहाँ मुखिया नारायण यादव, धनवार मुखिया राजेंद्र प्रसाद, कमल शंकर पंडित, राहुल प्रजापति, किशोरी मोहन पांडे, अर्जुन पंडित, रंजीत पांडे, पवन केसरी, मनोज कुशवाहा, अशोक यादव, राजदेव यादव, टिंकू भगत, दामोदर वर्मा, नंदलाल कुशवाहा व अन्य सदस्यों ने मिलकर किए थे। इस मेले में सभी अखाड़ों के अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष व सामाजिक व्यक्तियों ने संयुक्त रूप से मेला संपन्न कराने में भूमिका निभाई।

हजारीबाग का पदमा ओपी बनेगा थाना, देवघर हवाई अड्डा के पास खुलेगा ओपी

रांची, झारखंड। मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में संपन्न उच्चस्तरीय समिति की बैठक में हजारीबाग के पदमा ओपी को थाना का दर्जा देने का फैसला लिया गया। वहीं एक अन्य फैसले में देवघर हवाई अड्डा के पास नया पुलिस आउट पोस्ट खोलने पर मुहर लगायी गयी। गौरतलब है कि पदमा में पुलिस आउट पोस्ट काफी अर्से से कार्यरत है। बैठक में बताया गया कि पदमा ओपी का कार्य क्षेत्र काफी बड़ा है। इसका सृजन बरही थाना से दूर स्थित एनएच 30 के इलाके में विधि व्यवस्था के सुचारू संचालन के लिए किया गया था। लेकिन, अब यह इलाका विस्तृत आबादी वाले क्षेत्र में परिवर्तित हो गया है। इस इलाके में आपराधिक गतिविधियां भी उसी अनुपात में बढ़ी हैं। साथ ही सड़क हादसे में वृद्धि, बढ़ते उद्योग और उग्रवादियों की सक्रियता तथा सांप्रदायिक सद्भावना बिगाड़ने की कोशिशों के मद्देनजर पदमा ओपी को पूर्ण थाना में उत्क्रमित करने का निर्णय लिया गया। पदमा ओपी को थाना में उत्क्रमित करने में अनुमानित दो करोड़ 70 लाख रुपये खर्च होंगे। दूसरी ओर देवघर जिला के कुण्डा थानान्तर्गत देवघर हवाई अड्डा के कारण विमानपत्तन ओपी के सृजन का निर्णय लिया गया। इसके प्रस्ताव में गृह विभाग द्वारा बताया गया कि कुण्डा थाना से देवघर हवाई अड्डा की दूरी सात किमी. एवं मुख्यालय से 12 किमी. होने के कारण थाना का कार्य क्षेत्र काफी बड़ा हो जाता है। हवाई अड्डा का इलाका दुर्गम होने के कारण कुण्डा थाना से विधि व्यवस्था के संधारण में कठिनाई होती है। वहीं पिछले कुछ दिनों में आपराधिक घटनाएं भी बढ़ी हैं। इसके मद्देनजर आम लोगों की सुरक्षा के लिए उच्चस्तरीय समिति की बैठक में पुलिस आउट पोस्ट खोलने पर मुहर लगायी गयी। इस ओपी के सृजन में लगभग चार करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संपन्न उच्चस्तरीय समिति की बैठक में गृह विभाग की प्रधान सचिव वंदना दादेल, कार्मिक सचिव प्रवीण टोप्पो, ग्रामीण विकास सचिव के श्रीनिवासन, राजस्व सचिव चंद्रशेखर और आइजी हेडक्वार्टर मनोज कौशिक मौजूद थे।

स्वर्गीय ओम प्रकाश मिश्रा को दी गई श्रद्धांजलि, स्काउट झंडा झुकाकर किया गया नमन

रांची, झारखंड। द ऑल इंडिया बॉय स्काउट एसोसिएशन, झारखंड स्टेट ब्रांच के तत्वावधान में आज रांची के चटकपुर स्थित रूट राइडर चिल्ड्रन स्कूल के प्रांगण में जनरल सेक्रेटरी स्वर्गीय ओम प्रकाश मिश्रा के निधन पर भावभीनी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्काउट झंडा झुकाकर उन्हें सम्मानित किया गया और स्कूली छात्रों ने उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। विद्यालय के स्काउट विद्यार्थियों ने मिश्रा जी के आदर्शों और उनके दिखाए मार्ग पर चलने की शपथ ली। सभा में राज्य सचिव विक्रांत विश्वकर्मा, विद्यालय के प्रधानाध्यापक जयप्रकाश शर्मा, लक्ष्मी कुमारी, किरण कुमारी, चांद कुमारी, सुप्रिया कुमारी, लक्ष्मी गुप्ता समेत विद्यालय के शिक्षकगण एवं बड़ी संख्या में छात्र-छात्राएँ उपस्थित थे। राज्य सचिव विक्रांत विश्वकर्मा ने अपने श्रद्धांजलि संदेश में कहा कि स्वर्गीय ओम प्रकाश मिश्रा ने झारखंड में स्काउटिंग की नींव मजबूत की। उनके प्रयासों से राज्य में तीन ट्रेनिंग कॉन्फ्रेंस आयोजित किए गए और कई राष्ट्रीय स्तर के स्काउट कैम्प्स को सफलतापूर्वक संपन्न कराया गया।

भाजपा ही ऐसी पार्टी जिसमें बूथ अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है : सांसद रमेश अवस्थी

स्वतंत्र प्रभात

कानपुर। भाजपा क्षेत्रीय कार्यालय में मंगलवार को किदवई नगर विधानसभा एवं श्याम नगर के एक रिसॉर्ट में छावनी विधानसभा के सक्रिय सदस्यों का सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय में राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। सम्मेलन में वक्ताओं ने भाजपा का चुनावी एवं संगठनात्मक विचार, भारतीय राजनीति में भाजपा द्वारा लाया गया परिवर्तन और प्रधानमंत्री के रुप में नरेंद्र मोदी के साथ 11 वर्षों में विकसित भारत की यात्रा के संबंध में विस्तार से बताया। कार्यक्रम में सक्रिय सदस्यों को पार्टी की पंच निष्ठाओं के बारे में बताया गया। पीएम नरेंद्र मोदी सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। मुख्य अतिथि सांसद रमेश अवस्थी, जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह एवं विधायक महेश त्रिवेदी ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। मुख्य अतिथि सांसद रमेश अवस्थी ने कहा कि भाजपा में बूथ अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन सकता है। गर्मी में जहां अन्य दलों के कार्यकर्ता एसी कमरे में सो रहे हैं वहीं भाजपा कार्यकर्ता गांव और बूथों पर घर घर संपर्क कर मोदी योगी की उपलब्धियां घर-घर बता रहे हैं। मोदी- योगी के नेतृत्व भाजपा लगातार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ आगे बढ़ रही है। किदवई नगर विधायक महेश त्रिवेदी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को पूरा करने में सक्रिय सदस्यों की महत्व पूर्ण भूमिका है। पार्टी के सभी सक्रिय सदस्य, बूथ अध्यक्ष, बूथ कमेटी के सदस्य,पन्ना प्रमुख सहित सभी कार्यकर्ता खुद को मोदी और योगी का ध्वजवाहक मानकर अपने अपने बूथों पर काम करें। क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने कहा कि बूथ पर जीत ही चुनाव में विजय की गारंटी बनेगी।सक्रिय सदस्य बूथ पर निवास करने वाले वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित लोगों से निरंतर संपर्क रखें। प्रमुख रूप से दक्षिण जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह, एमएलसी अरुण पाठक,पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील बजाज, कौशल किशोर दीक्षित, रामदेव शुक्ल, डॉ वीना आर्या पटेल, मनीष त्रिपाठी,प्रकाश वीर आर्य,मनोज शुक्ला, अशोक त्रिपाठी, शिव पूजन सविता ,मंडल अध्यक्ष बिट्टू परिहार, दीपांकर मिश्रा, विनीत दुबे, दीपू पासवान आदि मौजूद रहे।

ओडिशा के मुख्यमंत्री की नई दिल्ली यात्रा से औद्योगिक क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धियाँ

स्वतंत्र प्रभात

नई दिल्ली। ओडिशा के माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी की दो दिवसीय नई दिल्ली यात्रा (7 और 8 अप्रैल, 2025) राज्य के औद्योगिक परिदृश्य को सशक्त बनाने की दिशा में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों के साथ संपन्न हुई। इस यात्रा के दौरान हुई रणनीतिक साझेदारियाँ और समझौते ओडिशा को पेट्रोकेमिकल और प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में एक मज़बूत औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होंगे।मुख्य आकर्षण के रूप में, ओडिशा सरकार ने नई दिल्ली में देश के अग्रणी औद्योगिक समूहों के साथ कई उच्च-मूल्य के समझौता ज्ञापनों (रूश्व्ह्य) पर हस्ताक्षर किए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण समझौता इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (ढ्ढह्रष्टरु) के साथ ओडिशा में डुअल-फीड नेफ्था क्रैकर परियोजना स्थापित करने हेतु किया गया, जिसकी अनुमानित लागत ?103090 करोड़ है। यह परियोजना लगभग 95,915 नौकरियों का सृजन करेगी और राज्य की पेट्रोकेमिकल क्षमता एवं विनिर्माण अवसंरचना को नई ऊँचाइयों पर ले जाएगी।मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी ने अपने मुख्य भाषण में कहा॰ आज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ किया गया रूश्व्ह्य ओडिशा की औद्योगिक यात्रा में एक ऐतिहासिक क्षण है। यह हमारे साझा दृष्टिकोण और ओडिशा की क्षमता में विश्वास का प्रतीक है। पारादीप, अपनी रणनीतिक स्थिति और उन्नत अवसंरचना के साथ, पश्चिम के दहेज की तरह एक परिवर्तनकारी औद्योगिक केंद्र बनने को तैयार है। ओडिशा तैयार है आपका स्वागत है। यही समय है, सही समय है। यात्रा की प्रमुख झलकियाँ॰ रूश्व्ह्य हस्ताक्षर और मेगा रोड शो ॰ कार्यक्रम की शुरुआत ओडिशा के मुख्य सचिव श्री मनोज आहूजा के स्वागत भाषण से हुई, जिसके बाद IOCL के चेयरमैन श्री ए.एस. सहनी ने संबोधित किया। रासायनिक क्षेत्र की पारिस्थितिकी पर एक वीडियो और उद्योग एवं MSME के अतिरिक्त मुख्य सचिव श्री हेमंत शर्मा द्वारा प्रस्तुतिकरण ने ओडिशा की औद्योगिक विकास रणनीति को प्रस्तुत किया ढ्ढह्रष्टरु के साथ डुअल-फीड नेफ्था क्रैकर परियोजना हेतु हुए समझौते को कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण पल माना गया। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत 58,042 करोड़ के निवेश के साथ 24,000 रोजगार के अवसर उत्पन्न होने की उम्मीद है।IOCL के अलावा, इंडियन स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व्स लिमिटेड (ISPRL) और पेट्रोनेट LNG के साथ भी अहम समझौते किए गए, जो राज्य के लिए एक रणनीतिक औद्योगिक स्थिति को दर्शाते हैं। कुल 13 रूश्व्ह्य पर हस्ताक्षर किए गए, जिनका कुल निवेश मूल्य 1,03,090 करोड़ है और जिनसे लगभग 95,915 रोजगार के अवसर सृजित होने की संभावना है।

महेशपुर में गाजे-बाजे के साथ धूमधाम से निकली रामनवमी शोभायात्रा

स्वतंत्र प्रभात

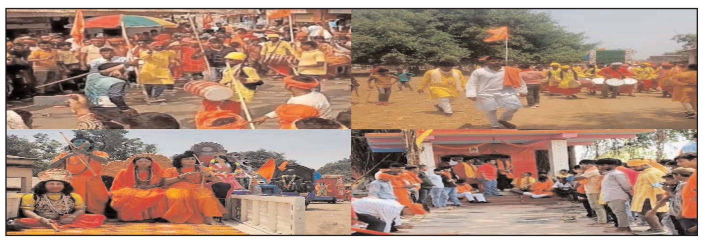

महेशपुर, झारखंड। रामनवमी के पावन अवसर पर महेशपुर प्रखंड मुख्यालय में सार्वजनिक रामनवमी अखाड़ा समिति की ओर से भव्य शोभायात्रा निकाली गई। इसकी शुरुआत श्री श्री 1008 बूढ़ा बाबा महेश्वरनाथ शिव मंदिर से विधिवत शस्त्र पूजन के साथ हुई। हजारों की संख्या में श्रद्धालु मंदिर परिसर में एकत्र हुए और तासा-बाजा की गूंज एवं भक्ति गीतों की धुन पर झूमते हुए शोभायात्रा में शामिल हुए। जय श्री राम, हर हर महादेव और भारत माता की जय के नारों से पूरा महेशपुर गूंज उठा। शोभायात्रा मार्ग में मोहल्लेवासियों ने पुष्प वर्षा कर श्रद्धालुओं का स्वागत किया। जगह-जगह ठंडा शरबत और पानी की व्यवस्था की गई थी। खास बात यह रही कि महेशपुर जुम्मा मस्जिद कमेटी की ओर से भी राम भक्तों के बीच शरबत एवं पानी की बोतलें वितरित की गई, जिसने आपसी सौहार्द और भाईचारे का संदेश दिया। शोभायात्रा में अखाड़ा समिति द्वारा तलवारबाजी, लाठीबाजी सहित कई पारंपरिक कौशलों का प्रदर्शन किया गया। आकर्षक झांकियों में श्रीराम, माता सीता, लक्ष्मण एवं हनुमान की प्रस्तुतियाँ विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। यात्रा शिव मंदिर परिसर से शुरू होकर हाटपाड़ा, दत्तापाड़ा, बाजारपाड़ा, तिवारीपाड़ा, ग्वालपाड़ा, अंबेडकर चौक, मुस्लिम टोला, भगत सिंह चौक, थाना होते हुए पुनः मंदिर परिसर में संपन्न हुई। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखा। एसडीपीओ विजय कुमार, भूमि सुधार उपसमाहर्ता मनीष कुमार, वीडियो सिद्धांत शेखर यादव, सीओ संजय कुमार सिंह, थाना प्रभारी विर्कण कुमार सहित कई प्रशासनिक अधिकारी शोभायात्रा में मौजूद रहे। चप्पे-चप्पे पर महिला पुलिस बल और सुरक्षा जवानों की तैनाती थी। ड्रोन कैमरे की मदद से पूरे जुलूस की निगरानी की जा रही थी। इस अवसर पर रामनवमी समिति के अध्यक्ष गुंजन तिवारी, अमित अग्रवाल, विजय भंडारी, साधन ठाकुर, संदीप भगत सहित अखाड़ा समिति के बिकी राय, दीपक साहा, बमबम यादव, अनिकेत सिंह, विष्णु भगत, शिवम भगत, पीयूष कुमार, गुड्डू रजक, गुड्डू भगत, दलजीत सिंह, मनोज कुमार, आकाश दत्ता, सूरज कुमार, सोमेन घोष, अपूर्व राणा, राणा सिंह, सन्नी तिवारी सहित सैकड़ों की संख्या में राम सेना शामिल रही।

मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए कई अहम फैसले

स्वतंत्र प्रभात

रांची, झारखंड मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की अध्यक्षता में 08 अप्रैल 2025 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निर्णय में जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय अंतर्गत कार्यालयों के लिपिक/ लिपिक सह-टंकक/टंकक संवर्ग में नियुक्ति हेतु झारखण्ड राज्य जल संसाधन विभाग क्षेत्रीय लिपिकीय पदों पर भर्ती नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई। झारखण्ड मूल्यवर्धित कर अधिनियम, 2005 के साथ संलग्न अनुसूची II Part E के अन्तर्गत Aviation Turbine Fuel पर देय कर दर (वैट) में संशोधन की स्वीकृति दी गई। झारखण्ड अवर शिक्षा सेवा संवर्ग (प्राथमिक शाखा) के पदाधिकारियों को राज्य शिक्षा सेवा वर्ग -2 (निरीक्षी शाखा) के पद पर भूतलक्षी प्रभाव से प्रोन्नति की स्वीकृति दी गई। स्व0 सरयू प्रसाद चौधरी, भूतपूर्व झा0प्र0से0 (कोटि क्रमांक 197/03) के सेवावधि से संबंधित अवधियों, जिसे विभागीय आदेश संख्या 4817 दिनांक 16.08.2011 द्वारा पेंशन एवं उपादान के भुगतान के प्रयोजनार्थ गणना हेतु झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 236 के तहत असाधारण अवकाश के रूप स्वीकृत किया गया है, को ख्क्क हृश्. 487/2022 झारखण्ड राज्य बनाम राहुल शंकर में दिनांक 13.08.2024 को पारित न्यायादेश के आलोक में कर्तव्य अवधि मानते हुए वेतन भुगतान से संबंधित प्रस्ताव पर स्वीकृति दी गई। सरकारी अस्पतालों द्वारा विभिन्न स्वास्थ्य बीमा योजना से अधिकतम Claim की राशि प्राप्त कर अस्पतालों के बेहतर प्रबंधन एवं स्वास्थ्य सुविधाओं को Indian Public Health के मानक के अनुरूप करने के लिए अस्पताल प्रबंधन हेतु मार्ग-निर्देश निर्गत करने की स्वीकृति दी गई। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित आवासीय विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु तत्कालिक व्यवस्था के तहत् Service procurement के आधार पर अंशकालीन शिक्षकों से कार्य लिए जाने की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।

सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के लिए 10 विधेयकों को......

संघर्ष के समय, उन्हें आम सहमति और समाधान का अग्रदूत होना चाहिए, अपनी सूझबूझ और बुद्धिमत्ता से राज्य मशीनरी के कामकाज को सुचारू बनाना चाहिए, न कि उसे ठप करना चाहिए। उन्हें उत्प्रेरक होना चाहिए, अवरोधक नहीं। उनके सभी कार्य उनके उच्च संवैधानिक पद को ध्यान में रखते हुए किए जाने चाहिए। यह अनिवार्य है कि उनके सभी कार्य उनकी शपथ के प्रति सच्ची निष्ठा से निर्देशित हों और वे अपने कार्यों को ईमानदारी से निष्पादित करें। राज्य के संवैधानिक प्रमुख के रूप में राज्यपाल का दायित्व है कि वे राज्य के लोगों की इच्छा और कल्याण को प्राथमिकता दें और राज्य मशीनरी के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए ईमानदारी से काम करें। राज्यपाल को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए लोगों की इच्छा को विफल करने और तोड़ने के लिए राज्य विधानमंडल में अवरोध पैदा न करने या उस पर नियंत्रण न करने के प्रति सचेत रहना चाहिए। राज्य विधानमंडल के सदस्य राज्य के लोगों द्वारा लोकतांत्रिक परिणामों के परिणामस्वरूप चुने गए और लोगों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हैं। इसलिए लोगों की स्पष्ट पसंद, दूसरे शब्दों में राज्य विधानमंडल के विपरीत कोई भी अभिव्यक्ति संवैधानिक शपथ का उल्लंघन होगी।

फीस वृद्धि के विषय पर महेश मिश्रा राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय युवा चेतना मंच का दिल्ली सरकार को सुझाव

स्वतंत्र प्रभात

नई दिल्ली। फीस वृद्धि का विषय केवल डीपीएस सोसायटी की कुछ शाखाओं जैसे द्वारका, वसंत कुंज, रोहिणी, या महाराजा अग्रसेन, पीतमपुरा, सृजन स्कूल, इंद्रप्रस्थ वर्ल्ड स्कूल इत्यादि तक सीमित नहीं है। अधिकांश निजी विद्यालयों के अभिभावक इस समस्या से ग्रसित हैं। यदि सभी स्कूलों के नाम प्रकाशित किए जाएं, तो समाचार पत्रों के पृष्ठ भी कम पड़ जाएंगे वर्तमान में अधिकतर स्कूलों में 10% से लेकर 100% तक की अनधिकृत फीस वृद्धि की जा चुकी है शिक्षा निदेशालय द्वारा आदेश जारी किए जाने के बावजूद उन्हें जमीनी स्तर पर लागू नहीं किया जा रहा है। जिन अभिभावकों ने मान्य फीस का भुगतान किया है, उनके मासूम बच्चों पर अनुचित तरीके अपनाकर, जैसे कि पुस्तकालय में कैद करना, नाम काटकर, अगली कक्षा में प्रमोट न करके मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। यह न केवल शिक्षा के अधिकार का उल्लंघन है, बल्कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डाल रहा है।सरकार को इस गंभीर विषय पर शीघ्र कार्रवाई करनी चाहिए और शिक्षा निदेशालय के उन अधिकारियों पर दंडात्मक कार्यवाही करनी चाहिए जिनके नाक के नीचे निजी विद्यालय इस प्रकार के कृत्य कर रहे हैं। विद्यालयों की मान्यता रद्द करना कोई स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि बीते 77 वर्षों में किसी भी विद्यालय की मान्यता, आदेशों के बावजूद, वास्तव में रद्द नहीं हुई है। हम तथा अभिभावकगण भी इस उपाय के पक्ष में नहीं हैं। इसके स्थान पर विद्यालयों का सरकारी अधिग्रहण टेकओवर किया जाना चाहिए इसके अतिरिक्त, अभिभावकों को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि पीटीए सदस्यों का लोकतांत्रिक ढंग से चयन न होना, पुस्तकें व वर्दी की काफी अधिक कीमत, हर साल किताबों का बदलना, समय पर एन सी आर टी की किताबों का उपलब्ध न होना और खेल गतिविधियों की अनुपलब्धता इत्यादि काफी मुद्दे है जिस पर हम और अभिभावक सरकारों से स्थाई ठोस करवाई चाहते सरकारों को यह समझना होगा कि यह केवल एक अभिभावक या एक राज्य का विषय नहीं है, *यह भारत देश के 150 करोड़ नागरिकों का मुद्दा है,* क्योंकि हर व्यक्ति या तो अभिभावक है या भविष्य में होगा। *बच्चे कल के विकसित भारत की नींव है शिक्षा प्रत्येक भारतीय का नैतिक अधिकार है न कि व्यापार। अतः भारत सरकार और सभी राज्य सरकारों को मिलकर इस विषय पर गंभीरतापूर्वक और एकजुट होकर कार्य करना चाहिए। हम और सभी अभिभावक इस प्रयास में सरकार का पूर्ण समर्थन करने के लिए तत्पर है।

नवजात डीपीआरओ ने चार्ज संभाला तल्ख तेवरों से सहमे कर्मचारी

स्वतंत्र प्रभात

मथुरा । जनपद के नवागत जिला पंचायत राज अधिकारी धनंजय जायसवाल ने दिन मंगलवार को पदभार ग्रहण किया सभी कर्मचारियों से मिलते हुए उनकी कार्यशैली और पटल के बारे में जाना गौरतलब है कि तत्कालीन डीपीआरओ भ्रष्टाचार के मामले में दो माह पहले जेल जा चुकी हैं उन्हें हाई कोर्ट से अभी जमानत मिल गई है। नवजात डीपीआरओ ने चार्ज लेते ही सरकार के अनुसार तत्कालीन डीपीआरओ के मामले को डैमेज कंट्रोल करने के लिए कार्य कैसे करना है सभी कर्मचारियों पहले पटल की जानकारी लेते हुए सभी पेंडिंग कार्य को तत्काल करने को निर्देशित किया

कर्मचारियों से पटल के अनुसार कहा

1- कितना बजट जनपद को इस वर्ष आवंटित हुआ है

2- जनपद को इस वर्ष कितने शौचालय मिले हैं

3- सभी ग्राम पंचायत में कितने हैंडपंप खराब है और कितने रि-वोर हुए हैं इस वर्ष का ब्योरा 4- 1 अप्रैल 2024 से आज तक किसी कर्मचारी का वेतन पेंडिंग है 5- जनपद में कुल कितनी ग्राम पंचायतों को ई-रिक्शा प्राप्त हुए हैं इस वर्ष 5- जनपद की ग्राम पंचायत में हुई सोशल ऑडिट की रिपोर्ट इस वर्ष की इन सभी मामलों की रिपोर्ट मुझे शाम 6॰00 बजे तक प्राप्त हो जानी चाहिए श्री धनंजय मीडिया से रूबरू होने पर बताया कि सरकार की प्राथमिकता के अनुसार सभी ग्राम पंचायत को स्वच्छ रखा जाएगा और ग्राम पंचायत में पानी की कमी को पूरा किया जाएगा

श्री-श्री चैत्र रामनवमी स्वागत समिति द्वारा पुष्पवर्षा एवं स्वागत सम्मान किया

स्वतंत्र प्रभात

हजारीबाग, झारखंड-श्री श्री चैत्र रामनवमी स्वागत समिति के तत्वावधान में रामनवमी के पावन अवसर पर भव्य शोभायात्रा में स्वागत सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस शुभ अवसर पर शहर के विभिन्न अखाड़ाधारियों एवं अतिथियों का स्वागत समिति द्वारा गर्मजोशी से किया गया। समिति के सदस्यों ने अखाड़ा में शामिल राम भक्तों पर पुष्पवर्षा कर उनका उत्साहवर्धन किया। मंच से माइक के माध्यम से तथा समिति के सदस्यों द्वारा लगातार अखाड़ाधारियों को प्रोत्साहित करते हुए उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी , ताकि वे बिना किसी रुकावट के अपने गंतव्य तक शीघ्र पहुंच सकें। रामनवमी से एकादशी की सुबह, समिति द्वारा हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को बिस्कुट, पानी एवं चिप्स का वितरण कर सेवा भावना का परिचय भी दिया गया। समिति के अध्यक्ष टोनी जैन ने कहा की समिति पिछले 3 वर्षों से लगातार अपनी सेवा दे रही है इसमें हमारे सभी सदस्यों का योगदान रहता है रामनवमी महापर्व में हम लोग अपना जितना योगदान हो सके करते हैं, जिससे हमारा यह पर्व आपसी भाईचारे समर्पण और श्रद्धा का प्रतीक बनकर उभरे। मंच पर कई गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति ने समारोह की शोभा को और भी बढ़ा दिया। इनमें प्रमुख रूप से हजारीबाग के प्रथम सांसद यदुनाथ पांडेय, सिविल सर्जन, पुलिस उपाधीक्षक, कांग्रेस नेता मुन्ना सिंह, कोमल राज रौनियार समाज के अध्यक्ष मनोज नारायण भगत, सद्भावना मंच के काजू भैया, मनोज गोयल, तथा मंच के तमाम सदस्य पूर्व उपमहापौर आनंद देव, ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमरदीप यादव, महासमिति के अध्यक्ष बसंत यादव, भाजपा जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह, अशोक यादव, दामोदर सिंह, हिंदू प्रचारक अजय दास, इंद्र नारायण कुशवाहा, कयुम अहमद, तनवीर जी, रणधीर पांडेय, संरक्षण समिति के अध्यक्ष प्रशांत प्रधान, हिंदू राष्ट्र संघ अध्यक्ष शशि केसरी, अनुपम सिंहा, सोनू कुमार, राकेश भैया सहित अन्य गणमान्य व्यक्तियों का नाम शामिल है। समिति के सदस्य सोनू गुप्ता, आशीष सोनी, शेखर गुप्ता, अमित पांडे, मुकेश सिंह, विनीत जैन, मनमीत अकेला विशाल वाल्मीकि, अंकित अग्रवाल सहित सभी लोग उपस्थित रहे। समिति द्वारा महावीर मंडल क्लब, बिहार दुर्गा स्थान क्लब समेत विभिन्न क्लबों को तलवार एवं अंगवस्त्र भेंट कर उनका सम्मान किया गया। यह आयोजन नगर में आपसी भाईचारे, समर्पण एवं श्रद्धा का प्रतीक बनकर उभरा और समस्त नगरवासियों ने इसमें बढ़-चढ़कर भाग लिया।

रामनवमी जुलूस के दौरान कांग्रेस नेता मुन्ना सिंह ने किया रामभक्तों का भव्य स्वागत, महासमिति अध्यक्ष बसंत यादव का भी किया सम्मान, दिया प्रेम और सौहार्द का संदेश

स्वतंत्र प्रभात

हजारीबाग, झारखंड। हजारीबाग में रामनवमी का पर्व इस वर्ष भी श्रद्धा, उत्साह और भव्यता के साथ मनाया जा रहा है मंगलवार की सुबह ऐतिहासिक इंटरनेशनल रामनवमी जुलूस के साथ नगर का माहौल राममय हो उठा। इस पावन अवसर पर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मुन्ना सिंह ने जमा मस्जिद रोड पर पारंपरिक रीति से रामभक्तों, आकर्षक झांकियों और अखाड़ों में भाग लेने वाले प्रतिभागियों का पुष्पमालाओं से स्वागत किया। साथ ही उन्होंने रामनवमी महासमिति के अध्यक्ष बसंत यादव का भी हार्दिक स्वागत एवं सम्मान किया। सिंह ने उपस्थित श्रद्धालुओं को रामनवमी की शुभकामनाएं देते हुए आयोजन समिति की अनुशासित, भव्य और समर्पित व्यवस्था की सराहना की। उन्होंने कहा कि रामनवमी हमारी सांस्कृतिक पहचान, सामाजिक एकता और भाईचारे का प्रतीक है। यह पर्व प्रेम और सौहार्द का संदेश देता है, और हजारीबाग सदैव से इन मूल्यों का पालन करता रहा है।उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि कांग्रेस पार्टी शुरू से ही ऐसे आयोजनों का समर्थन करती रही है और सामाजिक समरसता बनाए रखने के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रही है। आपकों बता दें कि जुलूस में रंग-बिरंगी झांकियों, परंपरागत शस्त्र प्रदर्शन और रामभक्ति में लीन श्रद्धालुओं ने नगर को एक आध्यात्मिक रंग में रंग दिया। चारों ओर जय श्रीराम के उद्घोष और उल्लासपूर्ण वातावरण ने शहर को उत्सवमय बना दिया।

संक्षिप्त खबरें

गैस एजेंसी की गाड़ी से चोरी हुए 55 हज़ार रुपए, सीसीटीवी में दिखे दो बाइक सवार

सीतापुर मिश्रिख क्षेत्र एक गैस एजेंसी की पिकअप वाहन से 55 हजार रुपए की चोरी हुई है यह घटना सोमवार की देर शाम हरदोई-सीतापुर मार्ग पर स्थित कन्नौजिया गैस एजेंसी के बाहर हुई एजेंसी के केयरटेकर सुनील कन्नौजिया ने बताया कि पिकअप वैन गैस सिलेंडर की होम डिलीवरी करके लौटी थी चालक और कलेक्शन मैनेजर खाली सिलेंडर उतार रहे थे। इसी दौरान वाहन की आगे की सीट से नकदी से भरा बैग गायब हो गया बैग में उपभोक्ताओं से वसूली गई लगभग 55 हजार रुपए की राशि थी एजेंसी परिसर में लगे सीसीटीवी की जांच में दो बाइक सवार युवक बैग ले जाते हुए दिखाई दिए। एजेंसी संचालकों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आसपास के लोगों से पूछताछ की सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान की कोशिश की जा रही है पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को पकड़ने का आश्वासन दिया है!!

ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से खेत में लगी आग, दो बीघा गेहूं की फ़सल जलकर ख़ाक

सीतापुर लहरपुर कोतवाली क्षेत्र में एक किसान की गेहूं की फसल में आग लग गई नौवापुर गांव में मंगलवार सुबह यह घटना हुई किसान महमूद खां के खेत में लगे ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी से आग लगी आग लगते ही ग्रामीण मौके पर पहुंचे उन्होंने तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी प्रभारी अग्निशमन अधिकारी हंस कुमार सिंह के नेतृत्व में दमकल विभाग की टीम ने ग्रामीणों के साथ मिलकर आग पर काबू पाया लेकिन तब तक दो बीघा गेहूं की फसल जलकर राख हो चुकी थी। पीड़ित किसान महमूद खां ने बताया कि उन्होंने बिजली विभाग और राजस्व विभाग को भी घटना की सूचना दे दी है महमूद खां के पिता का नाम रऊफ खान है उनका आरोप है कि ट्रांसफार्मर से निकली चिंगारी ने उनकी फसल को नुकसान पहुंचाया है!!

जंगली जानवर के आतंक से ग्रामीण दहशत में, 4 दिन में दो सांड का शिकार, वन विभाग ने पिंजरा लगाने का दिया आश्वासन

सीतापुर जनपद सीतापुर के लहरपुर कोतवाली क्षेत्र में एक हिंसक जंगली जानवर ने चार दिनों में दो सांड को अपना शिकार बना लिया है। मंगलवार को रावल अदेसर गांव में मुनीम वर्मा के गन्ने के खेत में एक सांड का क्षत-विक्षत शव मिला ग्रामीण जब सुबह खेतों की ओर जा रहे थे तब उन्होंने शव को देखा इसके बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण लाठी-डंडों के साथ मौके पर पहुंचे उन्होंने तुरंत वन विभाग को सूचना दी। इससे पहले शुक्रवार को भी इसी गांव में कल्लू यादव के गन्ने के खेत के पास एक सांड का शिकार किया गया था। दो घटनाओं से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है वे वन विभाग की कार्यप्रणाली से नाराज हैं उप वन क्षेत्राधिकारी हरीश श्रीवास्तव ने बताया कि विभाग लगातार कॉम्बिंग कर रहा है। जंगली जानवर के पदचिन्ह मिले हैं उन्होंने किसानों और ग्रामीणों को सतर्क रहने और समूह में खेतों पर जाने की सलाह दी है वन क्षेत्राधिकारी अभिषेक सिंह ने घटनास्थल का निरीक्षण किया उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है जंगली जानवर को पकड़ने के लिए गांव में पिंजरा लगाया जाएगा वन विभाग की टीम लगातार गांव की निगरानी कर रही है!!

जीआईसी कॉलेज मैदान में पीएनजी पाइपों में लगीं आग, लाखों की पाइपे जलकर ख़ाक, दमकल विभाग ने पाया आग पर काबू

[illegible]

जनहित व्यापार मंडल के प्रतिनिधि मंडल ने किया हारौनी रेलवे क्रॉसिंग और निर्माणाधीन ब्रिज का निरीक्षण

व्यापारिक संगठन जल्द ही डीआरएम से मिलकर सौंपेगा ज्ञापन

स्वतंत्र प्रभात

लखनऊ। उत्तर प्रदेश जनहित व्यापार मंडल ने मंगलवार को हरौनी रेलवे क्रासिंग और निर्माणधीन ओवर ब्रिज का निरीक्षण किया। प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा की नेतृत्व में 15 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के निरीक्षण के दौरान साथ में क्षेत्रीय व्यापारी व स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश जनहित व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा के नेतृत्व में हरौनी रेलवे स्टेशन पर उत्पन्न समस्याओं को लेकर एक प्रतिनिधिमंडल हरौनी रेलवे स्टेशन के अधीक्षक राहुल पटेल से मुलाकात मिला और पुल के निर्माण में उत्पन्न समस्याओं के बारे में जाना। इस अवसर पर रेलवे अधीक्षक ने संगठन का सम्मान करते हुए पुल निर्माण में उत्पन्न सारी स्थितियों के बारे में अवगत कराया एवं उच्च सक्षम अधिकारियों से वार्ता कराई निर्माण धीन पुल के जूनियर इंजीनियर द्वारा यह आश्वासन दिया गया की पुल के नीचे की सड़क एक हफ्ते के अंदर दुरुस्त कराकर डामरीकरण करा दी जाएगी तथा बकाया जो कार्य पटरी के ऊपर जो पिलर लगने हैं वह एक माह के अंदर लगा दिए जाएंगे। इस जटिल समस्याओं को देखते हुए व्यापारिक संगठन द्वारा कार्य को तेजी से कराने के लिए अगले तीन दिनों में डीआरएम लखनऊ से भी मुलाकात की जाएगी एवं उन्हें एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। इस अवसर पर प्रदेश के महासचिव विनोद सिंह प्रदेश उपाध्यक्ष अतुल सिंह प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सरदार हरजीत सिंह विधानसभा सरोजिनी नगर प्रभारी जितेंद्र हजेला गौरी जनहित व्यापार मंडल के अध्यक्ष दिलीप रावत एयरपोर्ट व्यापार मंडल के उपाध्यक्ष राजेश दुबे प्रदेश कार्यालय प्रभारी नरेश सिंह रावत और हरौनी बाजार से राहुल तिवारी, अतुल सिंह माखन नवीन तिवारी, देवेंद्र सिंह ,अजय रावत, संजय रावत ,ज्वेलर्स वीरेंद्र रावत के साथ कई व्यापारी व क्षेत्रीय जनता उपस्थिति रही।

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के बयान को लेकर समाजवादी महिला सभा ने किया विरोध प्रदर्शन

.... समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह की अगुवाई में किया गया विरोध प्रदर्शन।
..... हजरतगंज स्थित गांधी प्रतिमा के सामने शुरू किया गया विरोध प्रदर्शन। ।

स्वतंत्र प्रभात

विनीत कुमार मिश्रा

लखनऊ। मंगलवार को समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष जूही सिंह की अगुवाई में समाजवादी महिला सभा की महिलाओं ने हजरतगंज, लखनऊ स्थित गांधी प्रतिमा पर काली पट्टी बांध कर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया । रेखा गुप्ता द्वारा समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करने के कारण यह प्रदर्शन शुरू किया गया। समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय महासचिव विजय लक्ष्मी समेत विरोध प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने रेखा गुप्ता से अपशब्दों के लिए माफी मांगने की मांग की और उनके इस्तीफे की अपील भी प्रदर्शन में की गई । प्रदर्शनकारियों ने रेखा गुप्ता शर्म करो और रेखा गुप्ता माफी मांगो जैसी तख्तियाँ उठाई और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के अपमान के खिलाफ विरोध दर्ज जताया । विरोध प्रदर्शन के दौरान जूही सिंह ने कहा कि भाजपा का दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक विरोधी और अलोकतांत्रिक चेहरा अब सबके सामने आ चुका है। उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव देश के सबसे लोकप्रिय और जनप्रिय नेताओं में से एक हैं, और उनका अपमान किसी भी दशा में जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। जूही सिंह ने प्रदर्शन कर रही महिलाओं की गिरफ्तारी पर भी विरोध जताया और इसे पुलिस का अलोकतांत्रिक रवैया करार देते हुए उक्त कृत्य को घोर निन्दा की गई । विरोध प्रदर्शन में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. नेहा यादव, किन्नर पायल सिंह, सुमैया राणा, काज़मीन जहाँ, जिलाध्यक्ष प्रेमलता यादव, नगर अध्यक्ष मुन्नी पाल, वंदना चतुर्वेदी, राजबाला रावत, रिंकी सिंह, उषा सेन, सुभांगी द्विवेदी, शर्मिला महाराज, फारूख जहां, महनाज ख़ान, ममता सिंह, वीणा रावत, निकहत सिद्दीकी, जाह्नवी सिंह यादव, पूजा यादव बुंदेलखंडी, रमा यादव, शीला यादव, ममता शर्मा, अंजू यादव, कालिंदी भारद्वाज, मनीशा साहा, लता जैसवार, सलमा, मीना यादव, अफसर जहां, सब्बू, शीबा खान, सुमन यादव, अंजू यादव सहित समाजवादी महिला सभा की प्रमुख महिलाएं मौजूद रही ।

भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक गुट आबकारी आयुक्त कार्यालय पर शुरू किया अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन , हटाई जाएगी शराब की दुकान

..... भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक गुट के जिलाध्यक्ष राजेश रावत की अगुवाई में मेहनत रंग लाई ।
...... विवादित स्थल पर 7 दिन बाद हटाई जाएगी शराब की दुकान ।

स्वतंत्र प्रभात

विनीत कुमार मिश्रा

लखनऊ। मंगलवार को राजधानी लखनऊ के आबकारी आयुक्त कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने अपनी मांगों को लेकर के आबकारी आयुक्त को सम्बोधित ज्ञापन कार्यालय पर सौंपा । भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के जिलाध्यक्ष राजेश रावत की अगुवाई में पहुंचे सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने आबकारी विभाग द्वारा आवंटित दुकान इंदिरा नगर थाना क्षेत्र के अमराई गांव में जहां पर हनुमान मंदिर और छात्र छात्राओं का कोचिंग सेंटर व मेडिकल भी संचालित हैं वहीं पर शराब की दुकान होने के कारण स्थानीय लोगों में दिन पर दिन आक्रोश बढ़ता जा रहा है । पूर्व में भी अराजनैतिक संगठन के द्वारा शिकायत दर्ज कराई जा चुकी लेकिन मामले का संज्ञान नहीं लिया गया जिसके चलते भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक गुट ने शराब की दुकान उक्त स्थान से ना हटाए जाने तक अनिश्चितकालीन कालीन धरना शुरू कर दिया भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के जिलाध्यक्ष राजेश रावत ने बताया कि आबकारी विभाग द्वारा आवंटित दुकान जहां पर मंदिर , कोचिंग सेंटर व मेडिकल सेंटर है वहीं पर शराबियों के जमावड़ा होने के कारण स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है जब तक शराब की दुकान नहीं हटाई जाएगी तब तक यूनियन अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठी रहेगी एवं इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आबकारी विभाग की होगी । वहीं देर शाम को भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक के अनिश्चितकालीन धरने की सुगबुगाहट को देखकर दुकानदार शशि ने आबकारी आयुक्त को प्रार्थना पत्र देकर उक्त शराब की दुकान हटाए जाने का 7 दिन का समय मांग कर अन्य स्थान पर शराब की दुकान संचालित करने का आग्रह किया जिसको देखकर किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया एवं अनिश्चितकालीन धरना समाप्त कर दिया ।

विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने निकाली भव्य शोभायात्रा

स्वतंत्र प्रभात

मलिहाबाद, लखनऊ। मलिहाबाद में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के तत्वाधान में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। आपको बता दें कि मंगलवार को माथे पर भगवा रंग की टोपी व पगड़ी, ललाट पर पीला चंदन और हाथ में भगवा ध्वज के साथ शोभा यात्रा निकली तो पूरा क्षेत्र जय श्री राम के जयघोष से गूंजने लगा। यात्रा मुंशीगंज स्थित श्री त्रिवेणी शिवालय से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा विशाल शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ,जो क्षेत्र के प्रमुख चौराहों मार्गों से निकली।यात्रा में डीजे बज रहा था,श्री राम के गानों से लोग नाच रहे थे।यात्रा का जगह -जगह फूलों से स्वागत किया गया।यात्रा में लोग चप्पा-चप्पा गूंजेगा श्रीराम के जयकारों से, पूरा भारत भर जाएगा राम के दीवानों से, एक ही नारा एक ही नाम जय श्रीराम जय श्री राम का जयघोष करते हुए पैदल चल रहे थे। इस मौके गौ रक्षा प्रमुख सूरज सिंह ने कहा कि राम ही इस देश के राष्ट्र हैं,और हम सभी को मर्यादा के आदर्शों का पालन करना चाहिए। समय समय पर एकजुट होकर सनातनी होने का अहसास दिलाना चाहिए।इस मौके पर भूपेंद्र अर्कवंशी, रवि राजपूत, सुनील अर्कवंशी, सुनील शर्मा, प्रमोद अर्कवंशी, पुतान,हरिशंकर, अक्षत तिवारी, अर्पित सोनी,सुशील रावत, डॉ विनोद रावत, आकाश सिंह,सहित जिले व प्रखंड के पदाधिकारी व कार्यकर्ता शामिल रहें।

अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई जेसीबी समेत 5 ट्रैक्टर जब्त, खनन अधिकारी ने रात में की छापेमारी

स्वतंत्र प्रभात

[illegible]

अभाविप बिसवां की जिला समीक्षा योजना बैठक संपन्न

बिसवां सीतापुर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद बिसवां जिले की जिला समीक्षा योजना बैठक तीन सत्रों में ऋ्य तन्नह्रष्ठ ॥ह्ज्ञश्चरु के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में प्रमुख रूप से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत कार्यालय मंत्री आकाश शुक्ल, एवं विभाग संगठन मंत्री अजय प्रताप शुक्ल, विभाग संयोजक अमन अवस्थी की उपस्थिति रही। बैठक का शुभारंभ प्रांत प्रवासी आकाश शुक्ल, जिला प्रमुख गोपाल सिंह, जिला संयोजक वैष्णवी सिंह ने स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। बैठक कुल तीन सत्रों में सम्पन्न हुई। जिला समीक्षा योजना बैठक में पूर्व वर्ष की विद्यार्थी परिषद के द्वारा किए गए कार्यों की समीक्षा हुई एवं आगामी सत्र 2025-26 की वार्षिक योजना बनी। इस अवसर पर प्रमुखता से जिला संगठन मंत्री अभिषेक ओझा, जिला सह संयोजक नीरज यादव, प्रांत कार्यकारिणी सदस्य दीपांशी मिश्रा एवं धर्मेंद्र मिश्रा, तहसील संयोजक बिसवां अंकुर बाजपेई, सह तहसील संयोजक आकाश बाजपेई, नगर मंत्री बिसवां मुकेश द्विवेदी, नगर मंत्री रेउसा हर्षित अवस्थी, नगर सह मंत्री महमूदाबाद आदर्श अवस्थी, नगर मंत्री रामपुर मथुरा अमन दीक्षित, अनुराग मौर्य,

100 करोड़ का नया जिला अस्पताल डीएम ने किया स्थल निरीक्षण, एक सप्ताह में मांगा संशोधित लेआउट प्लान

स्वतंत्र प्रभात

सीतापुर जनपद सीतापुर में 99.89 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नए जिला चिकित्सालय का निर्माण जल्द शुरू होगा जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने प्रस्तावित स्थल का निरीक्षण कर लेआउट प्लान की समीक्षा की डीएम ने कार्यदायी संस्था को कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए उन्होंने कहा कि नए भवन के निर्माण में सभी मानकों का पालन किया जाए। आवागमन के लिए पर्याप्त चौड़े मार्ग और वैकल्पिक रास्ते बनाए जाएं पार्किंग व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। मरीजों के वाहनों, एम्बुलेंस और अन्य सेवा वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग स्थल का प्रावधान किया जाए। मल्टीस्टोरी पार्किंग का प्रस्ताव भी मांगा गया है ओपीडी के लिए पर्याप्त जगह और मरीजों व तीमारदारों के लिए बैठने-ठहरने की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया आवासीय भवनों और ट्रामा सेंटर के लिए प्रस्तावित स्थलों का भी निरीक्षण किया गया। परशुराम चौक से जिला चिकित्सालय तक के वैकल्पिक मार्ग का भी जायजा लिया गया डीएम ने एक सप्ताह के भीतर संशोधित लेआउट प्लान प्रस्तुत करने के निर्देश दिए उन्होंने कहा कि यह जनपद की चिकित्सा सेवाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण परियोजना है इस दौरान मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. सुरेश कुमार, एसडीएम सदर अभिनव कुमार और लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के अधिकारी मौजूद रहे!!

कार्यालय ग्राम पंचायत नोहरेपुर विकास खण्ड-दरियाबाद, बाराबंकी

पत्रांक मेमो/मनरेगा/ग्रा0पं0-नोहरेपुर / सामग्री आपूर्ति/निविदा-प्रकाश/दरि0/2025-26 **08/04/2025**

-:अल्पकालीन निविदा सूचना :-

विकास खण्ड दरियाबाद के अंतर्गत ग्राम पंचायत नोहरेपुर बाराबंकी में मनरेगा योजना अंतर्गत जनहित में निम्नलिखित कार्य कराया जाना है जिसके लिए संलग्न बिल आफ क्वान्टिटी के अनुसार सामग्री आपूर्ति हेतु जीएसटी पंजीकृत फर्म मालिक ठेकेदार/आपूर्तिकर्ताओं से स्वीकृत दरो के अधीन निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सामान आपूर्ति की निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा फार्म संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय से दिनांक 09-04-25 से 24 -04-25 तक किसी भी कार्य दिवस में निर्धारित धनराशि जमा करके प्राप्त किया जा सकते हमोहरबन्द निविदायें दिनांक 24.4.2025 को प्रातः 10 से 02 बजे अपरान्ह तक निविदा बॉक्स में डाली जाएगी तथा दिनांक 24.4.2025 को ही संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय पंचायत भवन में उपस्थित निविदाओं निविदा दाताओं के समक्ष ग्राम पंचायत की निविदा समिति के द्वारा समय 3:00 बजे खोली जाएगी

क्र0 सं0	ग्राम पंचायत का नाम	कार्य का विवरण	कार्य की मात्रा	सामग्री की जीएसटी सहित लागत (रू0 लाख मे)	आपूर्ति ली जाने सामग्री का विवरण	धरोहर राशि (रू0 मे)	निविदा मूल्य	अवधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नोहरेपुर	पेन्टेड रोड से रघुराज के घर होते हुए रिंकू माली के घर तक नाली व इण्टरलांकिग निर्माण 3148012044/RC/9584862	165× 3.30	9,98,530	गिटटी, मौरंग, बालू, सीमेन्ट,, सरिया, इन्टरलाकिंग ईट इत्यादि	2 प्रतिशत	500	03 माह
2	नोहरेपुर	रामसुख के घर से अरविन्द गौतम के घर तक इण्टरलांकिग निर्माण कार्य 3148012044 /RC/95848625	190× 3.30	9,97,794	गिटटी, मौरंग, बालू, सीमेन्ट,, सरिया, इन्टरलाकिंग ईट इत्यादि	2 प्रतिशत	500	03 माह

1. धरोहर राशि का राष्ट्रीकृत बैंक/पोस्ट आफिस द्वारा निर्गत डिमाण्ड ड्राफ्ट/पे-आर्डर्स/प्रतिभूति प्रमाण जो पंचायत नोहरेपुर विकास खण्ड दरियाबाद के नाम बन्धक करते हुए निविदि फार्म के साथ संलग्न करना होगा।
2. आपूर्तिकर्ता को संलग्न बिल आफ क्वान्टिटी के अनुसार उपरोक्त वर्णित सामग्री की आपूर्ति सम्बन्धित सचिव / प्रधान तकनीकी सहायक/अवर अभियन्ता के द्वारा बताये गये निर्दिष्ट समय स्थान पर सामग्री आपूर्ति करना होगा।
3. आपूर्ति की गयी सामग्री का मनरेगा योजनान्तर्गत धनराशि उपलब्ध होने पर ही नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी, विलम्ब आदि के लिए कार्यर्यादायी संस्था उत्तरदायी नही होगी।
4. जी0एस0टी0 पंजीकृत बिल ही मान्य होगा।
5. विभिन्न प्रकार के शासकीय करों के भुगतान का दायित्व आपूर्तिकर्ता का होगा।
6. आपूर्ति की गयी समाग्री की गुणवत्ता मानक के अनुरूप करने के उत्तरदायित्व आपूर्तिकर्ता होगा।
7. आपूर्ति की गयी सामग्री के भाडा/किराये का अलग से भुगतान देय नही होगा।
8. निविदा स्वीकृत होने पर सम्बन्धित फर्म मालिक ठेकेदार/आपूर्तिकर्ताओं से अनुबन्ध निष्पादित हो जाने पर पंचायत नोहरेपुर मे उपरोक्तानुसार/प्राक्कलित/स्वीकृत सामग्री सम्बन्धित सचिव/प्रधान/ तकनीकी सहायक / अभियन्ता के निर्देशानुसार उनके द्वारा निर्दिष्ट समय/स्थान पर सामग्री आपूर्ति करने पर विफल रहने पर धरोहर जब्त करने का ग्राम पंचायत का होगा।
9. सामग्री आपूर्ति का बिना कराण बताये अनुबन्ध निरस्त करने का अधिकार सचिव/प्रधान/निविदा समिति नोहरेपुर में निहित होगा।

तकनीकी सहायक
ग्रा0 पं0 नोहरेपुर
दरियाबाद, बाराबंकी।

सचिव
ग्रा0 पं0 नोहरेपुर
दरियाबाद, बाराबंकी।

प्रधान
ग्रा0 पं0 नोहरेपुर
दरियाबाद, बाराबंकी।